

खण्ड-07 सत्र-05
अंक-55

21 फरवरी, 2024
बुधवार
02 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा
पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

राज कुमार
सचिव
RAJ KUMAR
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप-सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 बुधवार, 21 फरवरी, 2024/02 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-55

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-41
3.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	42-85

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 बुधवार, 21 फरवरी, 2024/02 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-55

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. श्री अजेश यादव | 11. श्री जरनैल सिंह |
| 2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी | 12. श्री कुलदीप कुमार |
| 3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए. | 13. श्री महेंद्र गोयल |
| 4. श्री अब्दुल रहमान | 14. श्री मुकेश अहलावत |
| 5. सुश्री भावना गौड | 15. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर |
| 6. श्री बी. एस. जून | 16. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस |
| 7. श्री दिनेश मोहनिया | 17. श्री प्रकाश जारवाल |
| 8. श्री दुर्गेश कुमार | 18. श्री राजेश गुप्ता |
| 9. श्री हाजी युनूस | 19. श्री राजेन्द्र पाल गौतम |
| 10. श्री जय भगवान | 20. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों |

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 21. श्री राजेश ऋषि | 30. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान |
| 22. श्री रोहित कुमार | 31. श्री महेन्द्र यादव |
| 23. श्री संजीव झा | 32. श्री मदन लाल |
| 24. श्री सोमदत्त | 33. श्री नरेश यादव |
| 25. श्री शिवचरण गोयल | 34. श्री प्रलाद सिंह साहनी |
| 26. श्री सोमनाथ भारती | 35. श्री प्रवीण कुमार |
| 27. श्री सही राम | 36. श्री ऋतुराज गोविंद |
| 28. श्री एस. के. बग्गा | 37. श्री सुरेंद्र कुमार |
| 29. श्री विनय मिश्रा | 38. श्री विशेष रवि |

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 बुधवार, 21 फरवरी, 2024/02 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-55

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। 280 श्री अजय दत्त जी (अनुपस्थित), श्री सुरेंद्र कुमार जी (अनुपस्थित), श्री बी. एस. जून, शुरू करिये।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री बी.एस. जून: सर बिजवासन विधान सभा का 75 परसेंट एरिया डिपेंड करता है पानी के लिये बोरेवेल या वाटर टैंकर से। बाकी एरिया 25, 20 परसेंट जो है वो नार्मल सप्लाई है। एक बिजवासन गांव में एक शुरू किया था यूजीआर सितम्बर 2018 में और उसकी कंप्लीशन डेट थी 18 मंथ, मतलब मार्च 2021 में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन 5-6 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उसका सिविल वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिकल वर्क तो बाद की बात है। सर ज्यूं बड़े प्रोजेक्ट डिले होंगे, कोस्ट भी बढ़ेगी, लोगों को परेशानियां भी

आयेंगी। तो मेरा जलमंत्री से आग्रह है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उनको टाईमली, रेगुलरली रिव्यू किया जाये और उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि वो समय पर कंप्लीट कर सकें और जिसमें कोस्ट भी बचती है। सर ये जो यूजीआर है ये बहुत बड़े एरिया को कैंटर करेगा, बिजवासन, समालखा, कापसहेड़ा और एडज्वाइनिंग एरियाज़ और उसके साथ जो रजोकरी का एरिया, जो महारौली कंस्टीट्यूएन्सी में पड़ता है उसमें भी इसका पानी जायेगा। लेकिन अगर जिस स्पीड से इसका काम चल रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि इस साल भी ये कंप्लीट कर पायेगा। समर सीजन बहुत जल्दी आने वाला है उस वक्त हमें और ज्यादा दिक्कतें आयेंगी इन एरियाज़ में पानी की। बोरवेल जितने हैं सर या तो पानी इतना खींच लिया गया जमीन से कि काम नहीं कर रहे और जो इल्लीगल बोर्स है उस पर एनजीटी का एक अभी ऑर्डर आया है कि 5 हजार के करीब बोरवेल जो हैं सील कर दिये जायें। दिल्ली जलबोर्ड उन पर कार्रवाई भी कर रहा है। अगर वो बोरवेल सारे सील हो गये सर बहुत बड़ा संकट पानी का उत्पन्न हो जायेगा। तो मेरी यही रिकवेस्ट है सर मंत्री जी से कि इस यूजीआर का कंप्लीशन जल्दी से जल्दी करायें और इसको स्टार्ट करायें ताकि इस समर सीजन में लोगों को इस एरिया में पानी की दिक्कत न हो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्यू वेरी मच।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार

का ध्यान ओल्ड एज पेंशन की ओर दिलाना चाहता हूं। 2018 से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली के हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिये आवेदन किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1993 में जब हम पहली बार विधान सभा में आये तब भी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के लिये साल के लिए एक हजार वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन रिकमंड करने की सुविधा दी गयी थी। पिछले सात साल से ओल्ड एज पेंशन वरिष्ठ नागरिकों को मिल नहीं रही है और दिल्ली की जो अनॉथराइज कालोनिज हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, पुनर्वास बस्ती हैं, गांव की जो एक्सटेंडिट आबादी है, इसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं और सरकार की ओर से जो 2000 रूपया हर महीने पेंशन दी जाती है ओल्ड एज पेंशन दी जाती है उसी से उन वरिष्ठ नागरिकों का गुजारा ठीक-ठाक से हो पाता है। तो मेरा आपके माध्यम से मैं दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली के ऑनरेबल समाज कल्याण मंत्री से मांग करता हूं कि पिछले सात सालों से जो ओल्ड एज पेंशन नहीं बना कर दी गयी है प्रत्येक विधान सभा में 7-7 हजार वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन मंजूर की जाये जिससे कि 2018 से लेकर 2024 तक का जो सभी विधायकों का जो एक-एक हजार लोगों को जो हर साल पेंशन मिलनी चाहिये थी वो मिली नहीं तो कम से कम ये पिछला जो बैकलॉग कहिये उसको पूरा किया जा सके। मैं आपके माध्यम से ये दिल्ली की सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से मैं ये मांग

करता हूं। मुझे अच्छा लगता कि यदि दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री विधान सभा में उपस्थित होते और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और केवल ये मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुद्दा नहीं है बल्कि दिल्ली के सभी विधायकों का ये मुद्दा है, सभी विधान सभा क्षेत्रों में बेचारे वरिष्ठ नागरिक चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग पुरुष हों, वो विधायकों के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं कि आखिर नई ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं बनाई जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से, दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि ओल्ड एज पेंशन बनाने का जो काम बंद कर रखा है उसको शुरू करें और 2018 से ले के 2024 तक की हर विधान सभा में सात-सात हजार वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन दी जाये यही मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और समाज कल्याण मंत्री से आग्रह करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, श्री मदन लाल जी, सही राम जी पहले, सही राम जी, सौरी।

श्री सही राम: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दो विद्यालयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पहला स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेहखंड गांव। जिसमें अध्यक्ष महोदय 82 क्लासरूम निर्माण किया जाना था जिसके लिये लगभग 30 करोड़ रुपये का आवंटन भी हो

चुका है लेकिन अभी तक संबंधित अधिकारियों की अनदेखी के चलते 82 क्लासरूम का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। अतः महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर 82 क्लासरूम का निर्माण कार्य शुरू करवाने की कृपा करें जिससे स्थानीय बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को और बेहतर किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, तकरीबन एक-एक पाली में एक-एक शिफ्ट में चार से साढ़े चार हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं, क्लासरूमों की बहुत सख्त जरूरत है और पिछले करीब दो साल से ये मामला लंबित है। मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो भी इस पर थोड़ा संज्ञान लेंगी। अध्यक्ष महोदय दूसरा स्कूल है मेरा सर्वोदय कन्या विद्यालय तुगलकाबाद गांव में, खेल सुविधाओं को लेकर दो साल पहले अनुरोध किया गया था, अधिक समय हो चुका है जिसमें दो सौ मीटर का एथलीट ट्रैक, लंबी कूद, वालीबाल कोर्ट, कबड्डी मैदान, हैंडबाल कोर्ट, खिलाड़ियों के लिये चेंजिंग रूम, दर्शकों के लिये बैठने की जगह शामिल है जिसके लिये लगभग 10 करोड़ रुपये का आवंटन भी हो चुका है लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं कर पाये हैं। अतः अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर तत्काल प्रभाव से कार्य को शुरू करवाने की कृपा करें जिससे अधिक से अधिक छात्र खेल के प्रति जागरूक होकर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये और कहना चाहूंगा कि तकरीबन दो और तीन साल से मामले लंबित हैं। जो भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं क्योंकि सरकार एजुकेशन पर इतना ध्यान दे रही है, इतना

बड़ा बजट सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही है तो संबंधित अधिकारी हैं जो इसके, जिनकी वजह से ये काम लेट हुआ है उनके खिलाफ भी मंत्री जी अभी कोई कार्रवाई के आदेश देंगी तो मुझे खुशी होगी क्योंकि बाकी के जो और साथी लोग विधायक बैठे हैं, मेरे सम्माननीय विधायक बैठे हैं, उनके भी काफी लोगों के ऐसे काम रूके हुए होंगे तो उसमें थोड़ा सचेत होकर जल्दी काम करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या को उजागर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कोई 369 लगभग गांव हैं उनमें से बहुत प्राचीन गांव है गढ़ी। कालकाजी मंदिर की तलहटी पर बसा ये गांव थोड़ी सी निचाई पर है जिसके कारण पहाड़ का सारा पानी गढ़ी गांव से होकर गुजरता है। पानी की निकासी का प्रबंध न होने के कारण और गांव के बीचों-बीच में एक बहुत बड़ा नाला जो लगभग 12 फुट चौड़ा था उसके कारण गांव की हालत इस समय बहुत दयनीय हो गयी है। कालांतर के बने इस नाले में अब आजकल इतना गंद जमा हो गया है वो चाहे बरसाती पानी का हो, चाहे बरसाती गंद का हो, और अब कई लोगों ने उस पर अपने सीवर की लाईनें भी मिला दी हैं जिसके कारण अब वो बरसाती नाला, नाला न रह कर मिट्टी का एक ठोस जमीन बन गयी है। तो अब ना उससे पानी की निकासी हो रही है और न ही सीवर की। गांव में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार फुट पानी भर जाता है और बरसात

के दिनों में तो लोगों के घरों में चार से पांच फुट पानी तक भी भरा रहता है। एमसीडी के दुलमुल रवैये के कारण क्योंकि इसकी जिम्मेवारी एमसीडी की है, लगातार पिछले काउंसलर्स लोगों को बहलाने-फुसलाने के लिये राजनीति करते रहे और उन्हें बहकाते रहे कि हम इसको ठीक करा रहे हैं। अभी हाल में 17 लाख रुपये के बजट से उस नाले के एक छोटे से हिस्से में कहूंगा, शायद उसका 5 परसेंट भी हिस्से की सफाई नहीं कर पाये और 17 लाख रुपये खत्म कर दिये। ऐसे में न एमसीडी के लोग या मैं कहूं पार्षद या एमसीडी विभाग न हमें करने दे रहा है न हमसे कोई बात करते हैं और न खुद कर पा रहे हैं जिससे लोगों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो गयी है, लोगों में बीमारी फैलाने की आशंका पैदा हो गयी है और पूरे के पूरे गांव में दसघरां का वो एरिया लोगों को गंदे पानी में से होकर गुजरने के लिये मजबूर कर रहा है। आज नई दिल्ली के ऐसे गांव में ऐसा हो जाये ये बहुत ही ज्यादा अचरज और अचम्भे की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उस गांव के इस नाले की समस्या के लिये जो, मैं तो कहूंगा अगर वो एमसीडी नहीं कर पा रही तो दिल्ली सरकार का कोई विभाग इसमें इनिशिएटिव ले और लोगों को उस गंदगी भरे साम्राज्य से निजात दिलाये। ये बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति हो गयी है और मुझे खतरा ये लगता है कि किसी दिन वहां महामारी फैल सकती है। आपने मुझे इस बारे में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्ष: हाजी युनूस जी।

श्री हाजी युनूस: धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जिसका अपना कोई रोड नहीं है। या तो करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत आता है या गोकुलपुरी विधान सभा के अन्तर्गत आता है। मेरी विधान सभा का जो एक रोड अग्रवाल स्वीट्स से और मुखिया मार्किट तक का है। मैं पहले भी दो तीन बार इस मुद्दे को सदन में उठा चुका हूँ। उस रोड से लाखों लोग सुबह से शाम तक आते जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, उस पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कुछ पार्ट उसका मुस्तफाबाद विधान सभा में आता है बाकी गोकल पुरी विधान सभा में आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली सरकार का कि उस रोड के ऊपर एक पुलिया थी बृजपुरी पुलिया, जिसपर मैंने पहले भी बताया था 11 हजार और 33 हजार की बिजली की लाईनें पड़ी होती थी लेकिन वो पुलिया इतनी बढ़िया बन गयी कि वहां की जनता तीनों विधान सभाओं की गोकलपुरी, मुस्तफाबाद, करावल नगर की जनता उस पुलिया से बेहद खुश है। पुलिया पर तो जाम नहीं लगता लेकिन इस रोड पर ऐसा जाम लगता है कि एमरजेंसी में अगर कोई मरीज हो तो वो भी समय से अस्पताल पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं कि अस्पताल जाते-जाते मरीज की रास्ते में ही डेथ हो गयी। इतना जाम रहता है, आजकल ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है, हम लोग रात में 11-11, 12-12 बजे जब लौटते हैं तब भी वहां से गुजरना मुमकिन नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लगता है वहां पर। तो अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है मैंने पहले भी एसडीएम वगैरह को और

एमसीडी में भी इसके लिये चौड़ीकरण के लिये पहले भी मैं इसके लिये बार बार, कई बार दे चुका हूँ। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि अगर ये रोड चौड़ा हो जाता है तो न सिर्फ वहां की जनता को राहत मिलेगी, बल्कि तीनों विधान सभाओं की जनता आपकी बेहद आभारी रहेगी। आपसे अनुरोध है कि जो भी संबंधित अधिकारी या हमारी माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जहां से भी मुमकिन हो सके, हम जानते हैं एमसीडी में हमारी सरकार है लेकिन स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, कुछ मजबूरियां हैं, अगर किसी भी तरह से ये काम मुमकिन हो सके तो मेरी जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान फुल्ल डिपार्टमेंट की एक मुख्य गतिविधि की तरफ दिलाना चाहती हूँ जिसके कारण उन सभी विधायकों को भी काम करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है जिन्होंने अपना एमएलए फंड फुल्ल डिपार्टमेंट को दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जनता के अनुरोध पर फुल्ल डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ काम तैयार करवाये जैसे साईन बोर्ड, वेलकम गेट, जिम, सिक््योरिटी गेट इत्यादि। अध्यक्ष महोदय, मैं 2015 और 2020 में भी विधायक बनी, मैंने इन दो टर्म्स के अंदर अपना एमएलए फंड अधिकांशतः फुल्ल डिपार्टमेंट को दिया। फुल्ल डिपार्टमेंट के द्वारा मेरे यहां जिम, झूले, टोटलर, बैल्ट, सिक््योरिटी गेट, वेलकम गेट, बूम बैरियर, गार्ड रूम, पोर्टा केबिन इत्यादि बहुत सारे काम किये गये।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह कुछ एस्टीमेट्स तैयार करवाये, अधिकारियों ने उस एस्टीमेट को यह कह कर पास नहीं किया कि जिस जगह पर काम करना है और वो भूमि जिस एजेंसी की है उससे पहले एनओसी लेकर आये जबकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। और देखा जाये तो अध्यक्ष महोदय ये असंभव सी बात है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह नियम कैसे बदल गया। पिछले 8 साल में तो फुल्ल डिपार्टमेंट ने हमसे कोई एनओसी नहीं ली, मेरे एमएलए फंड के कई काम अभी रोक दिये गये हैं। नये एस्टीमेट्स सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, शायद ऐसा कई विधायकों के यहां भी हो रहा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सभी साथी आपसे अनुरोध करते हैं कि इस नियम में तुरंत बदलाव किया जाये और हमारे एस्टीमेट्स को पहले की तरह सैंक्शन किया जाये। धन्यवाद।

...व्यवधान...

सुश्री भावना गौड़: आज तक कोई एनओसी नहीं दी हमने, 8 साल फुल्ल डिपार्टमेंट से काम करवाये हैं।

माननीय अध्यक्ष: भई, भावना जी, आपने अपनी बात रख ली ना।

सुश्री भावना गौड़: जी, जी।

माननीय अध्यक्ष: एक सैकिंड देखिये मेरी बात सुनिये किसी विधायक को इस विषय पर बोलना है तो कृपया हाथ खड़ा करके बोलें, ऐसे न बोलें कि सब खड़े हो गये। हां मैं मानता हूं सबकी समस्या होगी।

सुश्री भावना गौड़: सभी के हाथ खड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष: एक सैकिंड रूकिये जरा एक सैकिंड, हां महेंद्र गोयल जी हां।

श्री महेंद्र गोयल: अध्यक्ष जी, जब अनोथराइज्ड कालोनियों के अंदर हमें आईएंडएफसी के तहत करना होता है। अनोथराइज्ड कॉलोनी के अंदर एमसीडी कोई काम नहीं करती, कोई उसका एस्टीमेट नहीं बनाती, तो उसका सिर्फ चारा एक ही बचता है या तो आईएंडएफसी से काम करवाये या डीएसआईडीसी से करवाये। डिपार्टमेंट ने एक कलॉज लगा दिया कि एमसीडी से एनओसी लेकर आओ। एमसीडी से एनओसी हम किस बात की लेंगे। जब एमसीडी की वो जमीन नहीं है, एमसीडी का अधिकार क्षेत्र नहीं है उसके अंदर काम करने का, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, दिल्ली के कामों को अटकाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस समय और जानबूझ कर काम हो रहा है और मेरे ख्याल से नेता विपक्ष भी इस बात सहमत होंगे क्योंकि इनको भी पता है, इनके एरिये के अंदर भी ये दिक्कत आ रही होगी जरूर। मैं कहता हूं कि इसमें यदि नेता विपक्ष का भी स्पष्टीकरण लेंगे तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा हाउस इसमें एकमत है, सभी को समस्या पैदा हो रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है जो भावना गौड़ जी ने 280 के तहत अपनी समस्या रखी, ये पूरी दिल्ली की समस्या है। तो मैं भावना गौड़ जी को सैल्यूट करता हूं जो आप आज ये क्वेश्चन लेकर आए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: ऋषि राज जी। बस इस पर मैं दो नाम और दे रहा हूँ।

श्री राजेश ऋषि: अध्यक्ष जी, ये मुद्दा जो भावना जी ने उठाया है 280 में, ये सारी विधानसभाओं के अंदर ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो भी एजेंसी आज एमएलए फंड का यूज करने के लिए पैसा लेती है, एस्टीमेट बनाती है, उसके बाद ये स्थिति हो जाती है कि उसको एनओसी के लिए यूडी में जाना होगा, यूडी की ये टर्म एंड कन्डीशन्स हैं कि आप एनओसी लेकर आइये जिस जमीन पर आपने काम करना है। हमें समझ में नहीं आता, हमें अनॉथराज्ड कॉलोनियों में जो डीएसआईडीसी की जमीन पर काम करने के लिए भी एमसीडी।

माननीय अध्यक्ष: इसका समाधान भी बताइये ना साथ की साथ।

श्री राजेश ऋषि: सर इसका समाधान हम मंत्री जी बैठे हैं, हमें इनसे अनुरोध करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: ऋषि जी ये समस्या उठाना एक विषय है।

श्री राजेश ऋषि: जी।

माननीय अध्यक्ष: लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है ये भी तो रखिये साथ-साथ।

श्री राजेश ऋषि: सर हम वो ही कह रहे हैं कि यूडी को।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: नहीं महेंद्र जी बैठिए आप, ऐसे नहीं कुलदीप जी ऐसे नहीं मैं अलाउ करूंगा। आप बैठिए प्लीज।

श्री राजेश ऋषि: सर समाधान बता रहा हूं

माननीय अध्यक्ष: महेंद्र जी बैठिए, मैं अभी बात करता हूं।

श्री राजेश ऋषि: अध्यक्ष जी मंत्री जी बैठे हैं, यूडी ने ये गाइडलाइन बनाकर दी है, जो डिपार्टमेंट्स का कहना है कि यूडी से ये गाइडलाइन आई है कि एनओसी लेकर आए। मैं आपके द्वारा ये अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी जो ये गाइडलाइन बनाई है, जो 8 साल पहले नहीं थी, आज जो बनी है इसको रोका जाए क्योंकि ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, एमएलए फंड पड़ा का पड़ा रह जाएगा, यही हम सर कहना चाहते हैं और भावना जी ने ये बात सबके लिए उठाई है, भावना जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: देखिये माननीय सभी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, आज एक बजे का जो विषय है उसमें टाइम मैं काट नहीं सकता किसी कीमत पर और अभी चार, 280 में बाकी हैं, केवल बिधूड़ी जी, बिधूड़ी जी के बाद शिवचरण गोयल जी और विशेष रवि जी बस। बहुत संक्षेप में बिधूड़ी जी प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस सदन में सभी विधायकों की ये गम्भीर पीड़ा है, ये फैसला किस स्तर पर लिया गया है, किसकी मंजूरी है इसकी जानकारी भी इस

सदन को मिल जाए। मैं केवल, केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब तक अनॉथराइज्ड कॉलोनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं हो जाती है, हमारी यूडी मिनिस्टर भारद्वाज जी हैं, भारद्वाज जी आप बातचीत कर रहे हैं जरा सुन लीजिए थोड़ा सा।

....व्यवधान....

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं मैं बता रहा हूं ना। अनॉथराइज्ड कॉलोनी जब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं हो जाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस अनॉथराइज्ड कॉलोनी में काम कर नहीं सकती है और सरकार का जो फैसला है कि अनॉथराइज्ड कॉलोनीज में डीएसआईडीसी काम कर सकती है, फ्लड काम कर सकता है, इसमें यदि कहीं भी कोई रूकावट आ रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर सरकार को अगर मेरी कहीं सहायता या मदद की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो मैं हर स्तर पर मैं अपने सभी ऑनरेबल एमएलएज के साथ जहां चाहेंगे, वहां चलने के लिए तैयार हूं, ये सभी का, मतलब ये सभी के सामने ये संकट है इस संकट को मिल-बैठकर बातचीत करके इसका रास्ता निकालना चाहिए और ओनरेबल यूडी मिनिस्टर को बताना चाहिए कि ये मामला किस तरह से सुलझाया जा सकता सकता है, हम उस पर पूरा सहयोग देंगे।

माननीय अध्यक्ष: शिवचरण जी।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी, सौरभ जी। इसपर एक सैकंड अभी नहीं, अभी नहीं मैं कहूंगा आपसे।

श्री सौरभ भारद्वाज (स्वास्थ्य मंत्री): सर मैं मोटे तौर पर बता दूँ

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी एक मिनट बैठिए जरा दो लोगों को बोल लेने दीजिए, मैं आपसे, आप उत्तर दीजिएगा इसपर जरूर।

श्री शिवचरण गोयल: अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: संक्षेप में, बहुत संक्षेप में।

श्री शिवचरण गोयल: अभी गाइडलाइन आई है, एमसीडी डिपार्टमेंट से कि जो सिक्योरिटी गेट्स हैं, जो लगते थे और जो एक गम्भीर समस्या है कि आज क्षेत्र में लोग असुरक्षा से ग्रसित हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही और वो सिक्योरिटी गेट्स भी, उसके लिए भी एनओसी मांगनी शुरू कर दी और पूरा डिपार्टमेंट को रोक दिया गया है कि यहां आईएंडएफसी कोई काम नहीं करेगी और मुझे अभी जैसे ज्ञात हुआ है, संजीव भाई से की एल.जी. साहब से मीटिंग की गई और उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से एक पोल्टीकल मोटिवेटिड प्रोग्राम किया जा रहा है कि जिससे पूरी दिल्ली को ठप्प कर दिया जाए, विधायकों को काम करने ना दिया जाए, इसके ऊपर पूरा एक संज्ञान लेते हुए, जैसे हमारे विपक्षी नेता भी कह रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई

ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए और उसके ऊपर कोई ना कोई ठोस प्रोग्राम आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: विशेष रवि जी। उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री विशेष रवि: सर एक तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये समस्या सिर्फ अनॉथराइज्ड कॉलोनी की नहीं है बल्कि दिल्ली में जितनी भी कॉलोनिज है, जिस भी तरह की कॉलोनी है सब जगह दिक्कत है और सर ये भी बताना चाहूंगा आपको मैं ये ऐसा नहीं है कि एनओसी का ये जो इश्यू है ये आज ही पैदा किया गया या नियम अभी जोड़ा गया है। जब ये ओब्जेक्शन लगा तो मैंने गाइडलाइन मंगाई और गाइडलाइन मंगाकर देखा तो उसमें पहले से था कि एनओसी चाहिए हमारे को लेकिन पिछले 10 साल से कभी भी जो है उसपर जोर नहीं दिया गया, उसको मंडेटरी नहीं किया गया, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इसको मंडेटरी किया गया है। जब ये मंडेटरी कर दिया गया तो उसके बाद सर मैंने कुछ कामों को लेकर एमसीडी के अधिकारियों से बात करी की भई आप एनओसी दे दो इसके अंदर, अगर एमसीडी की एनओसी की जरूरत है तो दे दो आप। तो एकजीक्यूटिव इंजीनियर से बात करी, चीफ इंजिनियर से बात करी, कमिशनर से बात करी, सबने ये कहा कि सर हमारी पावर में नहीं है, अगर एनओसी चाहिए आपको तो वो हाउस से मिलेगी, मतलब एक गली बननी है हमारे यहां पर किसी के मोहल्ले के अंदर तो उसकी परमिशन, उसकी एनओसी हाउस से मिलेगी, एक बात। सर दूसरी दिक्कत इसमें ये है कि मान लीजिए

आपने बात की हल की, तो हमने ये सोचा था चलो कोई बात नहीं अब अगर एमसीडी से ही काम करवाना है, अगर एनओसी नहीं मिल रही है, फ्ल्ड डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है, डूसिब डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता तो एमसीडी से करवा लेते हैं। जब एमसीडी वालों को हमने कहा कि तुम बनाओ एस्टीमेट, तो उस उनके यहां कितनी बड़ी समस्या है कि वहां पर जो एक्जीक्यूटिव इंजिनियर की फाइनेंशियल पावर है, सिर्फ 5 लाख रुपए की है, यानि 5 लाख से ऊपर कोई भी आपको काम करना है, तो वो फाइल जायेगी 3 बार कमिशनर ऑफिस के अंदर और तीन बार कमिशनर ऑफिस के पास फाइल जाने का मतलब ये है कि एक गली बनने के लिए आपको सात से आठ महीने लगेंगे और वहीं फ्ल्ड डिपार्टमेंट वालों की पावर जो है 5 करोड़ की है एक्सईएन की, पीडब्ल्यूडी की जो है 2 करोड़ की है, एक करोड़ की है। तो यानि की अगर एमसीडी से काम कराना है तो वो सम्भव नहीं है और एनओसी से काम करना है तो वो सम्भव नहीं है। इस काम को लेकर मैंने माननीय मंत्री जी से हमारे प्रभारी दुर्गेश जी बैठे हैं इनसे पिछले कई महीने से फॉलोअप कर रहे हैं लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है और अगर इसका हल नहीं निकलेगा, तो अगर आप जो बजट देने वाले हैं 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए वाले तो वो पैसा, ऐसा का ऐसा रखा जाएगा कोई काम नहीं हो पाएगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सौरभ जी माननीय मंत्री।

श्री सौरभ भारद्वाज (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष जी, ये हमारी सरकार के आने से पहले अनॉथराइज्ड कॉलोनी के अंदर एमएलए लैड फंड से काम नहीं हुआ करते थे और इसी तरीके से जो कॉओपरेटिव सोसाइटीज है जिन्हें प्राइवेट सोसाइटी भी कहा जा सकता है, रोहिणी में हैं, द्वारका में हैं, हमारे यहां कई जगह हैं, उनमें भी एमएलए फंड से काम नहीं हुआ करता था। जब ये सरकार हमारी बनी तो हमने इसके अंदर तबदीलियों की और हमने कहा कि एमएलए लैड फंड से काम आप अनॉथराइज्ड कॉलोनी में भी करा सकते हो और प्राइवेट कॉलोनी में भी करा सकते हैं। भई जब एमएलए वोट मांगने तो सब जगह चले जाते हैं, अनॉथराइज्ड कॉलोनी के वोट ऑथराइज्ड हैं, काम उसके अनॉथराइज्ड हैं, कोओपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन करेगा सड़कों का काम, कौन लगाएगा बैंच, कौन लगाएगा झूले, सरकार को ही लगाने पड़ेगा और तो कोई नहीं लगा सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने ये फैसला किया और ये 2015 से लेकर अभी 2023 तक ये मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। अनॉथराइज्ड कॉलोनी के अंदर आप जिस एजेंसी से चाहें उससे वो काम करा लेते थे, छोटे-मोटे। देखिये सड़क का काम तो इरिगेशन फ़ुलड कंट्रोल और डीएसआईडीसी करता है, कैबिनेट नोट के अंदर ये फैसला हो रखा है और ये विभाजन हो रखा है कि ये कॉलोनी इनके पास है, ये कॉलोनी इनके पास उस हिसाब से चलता है। इसके अलावा जो छोटे-मोटे काम हैं जैसे किसी को लाइट लगवानी है, किसी को सिक्योरिटी गेट लगवाने है, किसी को वहां पर कुछ और छोटा-मोटा काम कराना है, वो काम एमएलए फंड से तीनों

ही एजेंसी से लोग करा लेते थे, ज्यादातर लोग फूलड से और एमसीडी से कराया करते थे। ठीक इसी तरीके से गांव वगैराह के अंदर अगर सड़कें होती थी तो एमसीडी से बनवा लिया करते थे, नहीं बनवाना चाहते थे तो फूलड से बनवा लिया करते थे और ये होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे यहां अपने गांव के अंदर मैंने एमएलए फंड से जब लगा कि एमसीडी के अंदर कोई तेज ऑफिसर है वो जल्दी काम करेगा तो मैंने एमसीडी को पैसा दे दिया, जब लगा कि एमसीडी वाले ढीला करते हैं, फूलड के अंदर ऑफिसर ठीक हैं, फूलड को दे दिया। दोनों से ही काम हुआ और बड़े अच्छे से काम हुआ। 2023 के अंदर कुछ ऑफिसरों ने मिलकर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। अब वो ऑफिसर कौन है, वो एमसीडी के ऑफिसर है और इरीगेसन फूलड कंट्रोल के ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि ये काम तो बड़ी तेजी चल रहे हैं, इनको किसी तरह से फंसाया जाए। तो कमिश्नर एमसीडी ने एक चिट्ठी फूलड कंट्रोल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखी जो अब इतने जो है अब वो एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं आशीष कुंद्रा जी, कि भई ये जो लैंड ओनिंग एजेंसी जिसकी है वो ही एजेंसी उसके अंदर काम करे, हालांकि मेरे लिखित आदेश थे कि इसके ऊपर. उन्होंने बोला कि वही काम करे और अगर दूसरा करे तो एनओसी। प्राथमिकता ये है कि काम वही करे जिसकी लैंड ओनिंग एजेंसी है और अगर ना करे तो उसकी एनओसी लो। मैंने इनको लिखित में दिया कि आप इसके ऊपर कोई ओर्डर मत निकालिएगा ये मल्टीपल एजेंसिज का मामला है, इसको आप मेरे अंदर सबकी मीटिंग करिएगा

उसके बाद कोई ऑर्डर लीजिएगा। मगर उसके बावजूद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरीगेसन फ्लड कंट्रोल या उन्होंने कहकर किसी नीचे वाले अक्सर से ये ऑर्डर निकालवा दिया। अब इस ऑर्डर की वजह से ये हो गया कि जहां पर गांव वगैरा के अंदर एमसीडी की जमीन है, लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, उन सड़कों की, उन गलियों की वहां पर इरीगेसन फ्लड ने एस्टीमेट बना लिए, कई जगह काम सैंक्शन हो गए, पैसा आ गया। अब उन्होंने बोला कि साहब ये एनओसी जब तक एमसीडी से नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं होंगे। एमसीडी बोलती है कि हमारे यहां तो एनओसी का कोई प्रोसेस ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहां ये कोई तरीका ही नहीं है कि कैसे एनओसी देना है, we do not have the process. तो कुल मिलाकर एमसीडी कमिश्नर और इरीगेसन फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ने मिलकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से, वर्ना अक्सरों को बैठकर सोल्युशन निकालना चाहिए था कि भई ये तरीका है इस तरीके से एनओसी मिलेगा, ये टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन के थ्रू मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। अब इसके अंदर तरीका क्या है, मैं असेंबली को बताना चाहता हूं। हमने इसी हाउस के अंदर कुछ सालों पहले एक रैजूलेशन पास किया था कि एमएलए फंड की टाइमलाइंस हमने तय की थी, इस हाउस ने तय की थी, उसके अंदर टाइमलाइन है। इतने दिनों में सैंक्शन होगा, इतने दिनों के अंदर वर्क ऑर्डर होगा, इतने दिनों में काम होगा, नहीं होगा तो वो प्रिविलेज माना जाएगा हाउस का, हाउस अपनी पावर इस्तेमाल करे। उन ऑफिसरों को बुलाये यहां

पर, उनसे पूछे प्रिविलेज कमेटी को थोड़ा मजबूत करो कि वो बुलाकर उनसे पूछे कैसे नहीं हुआ, पहले भी तो काम होते थे। ये षड्यंत्र तो अब अध्यक्ष जी चल रहे हैं। अब आते हैं जो दूसरी बात जो बोली है इन्होंने कि अब अनॉथराइज्ड कॉलोनी में कैसे काम हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका अनोथराइज्ड कॉलोनी के अंदर काम कराने का ये है कि आप फ्लड डिपार्टमेंट से करा लो, क्योंकि एमसीडी के अंदर तो जो है वो काम आपके फंसाने का जो है उद्देश्य दिखता है साफ-साफ सा। तो आप फ्लड से करा लो, कैबिनेट नोट है हमारा कि फ्लड जो है वहां पर। नहीं, वो मैं कह दूंगा फ्लड के अंदर कि फ्लड डिपार्टमेंट आपको अगर, आपका एस्टीमेट बनाकर देगा अनॉथराइज्ड कॉलोनी के अंदर तो उसके अंदर एमसीडी की एनओसी का कोई मतलब नहीं है, एमसीडी का कोई लेना-देना ही नहीं है वहां पर। एमसीडी का कोई लेना-देना नहीं है, वो हम उसको रिजोल्व कर देंगे, उसको हम रिजोल्व कर देंगे।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: झा साहब आप बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। आप मंत्री जी को बोलने दो एक बार फिर देखेंगे, मंत्री जी बोल रहे हैं बीच में आप बोल रहे हैं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी समय देता हूं, कोई तथ्य है, बिधूड़ी जी प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाज (स्वास्थ्य मंत्री): तो अध्यक्ष जी जो संजीव झा जी बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं उनको समय दूंगा आप, आप।

श्री सौरभ भारद्वाज (स्वास्थ्य मंत्री): एल.जी. कार्यालय के निर्देश पर कुछ हुआ है वो उसकी जानकारी मुझे फ्रैंकली नहीं है, ना मेरे पास वो ऑर्डर है, अगर वो किसी के पास जानकारी है तो रखे हाउस के अंदर।

माननीय अध्यक्ष: बताईये, अब बताइये संजीव जी, संजीव जी अब बोलिए, बहुत संक्षेप में, बस राजेश जी दो मिनट।

श्री संजीव झा: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा था, तो बेसिकली कल ही मेरे पास एक चिट्ठी आई जिसमें आशीष कुंद्रा जी ने सभी डिपार्टमेंट को लिखा है और उन्होंने ये मेशन किया है कि एलजी साहब के यहां सभी अधिकारी, सभी सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि सभी एजेंसी किसी भी अनोथराइज्ड कॉलोनी में काम करें, चाहे रेगूलराइज्ड कॉलोनी में काम करें, चाहे गांव में काम करे, वो एनओसी लेंगे। तो मेरा ये कहना है, एनओसी एमसीडी से लेंगे, वो कह रहे हैं कि to duplicacy of work को रोकने के लिए।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: भई, जून साहब ऐसे नहीं चल पाएगा, वो गम्भीर विषय रख रहे हैं आप लोग अपनी बात में लगे हैं।

....व्यवधान....

श्री संजीव झा: ये 14/2 की मीटिंग है, during a meeting held under the chairmanship of Hon'ble LG Delhi attended by the HOD of various departments, Commissioner, MCD pointed out that I&FC's planning executing development work without taking NOC from the land owning agency that is MCD. Initiation of work under the jurisdiction of other land owning agency without taking NOC may cause un-necessary wastage of effort as more than the agency's working on the same project simultaneously and may also lead the duplication and litigation in certain cases. All concerned are directed to ensure that no work shall be initiated, executed without NOC from the respecting land owing agency. Ashish Kundra, Pr. Secretary (I&FC). ये 14 तारीख को मीटिंग हुई है। तो बिधूड़ी जी मैं आपसे यही कहना चाहता था, एक मिनट, बिधूड़ी जी एक मिनट। मैं माननीय हमारे एलओपी से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये ईल्लिगल ओर्डर है और अगर parallel सरकार के, सरकार के parallel अगर एलजी साहब एक executive order पास करेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी, एक बात। दूसरी बात आज ही मेरे ही constituency में एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब अनॉथराइज्ड कॉलोनी में जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं दी गई है, मैं आज से तीन महीना पहले जाकर इनको सारी समस्याएं बताई थी, वो समस्या देखने नहीं आ रहे और पता नहीं वो क्या करने आ रहे हैं। तो फिर आप एक चुने हुए representative के

अथॉरिटी को सुपरसीड कर रहे हैं, कैसे दिल्ली चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, कैसे सदन चलेगा? तो एलजी साहब इस सदन को सुपरसीड कर रहे हैं, एलजी साहब गवर्नमेंट को सुपरसीड कर रहे हैं और पैरलर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: हो गया।

श्री संजीव झा: आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ऋतुराज जी इसकी एक हार्डकॉपी निकलवाकर सदन पटल पर रखिए।

श्री संजीव झा: सदन के साथ ही इसकी निंदा करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: इसकी एक हार्डकॉपी निकलवा के सदन पटल पर रखे।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: नहीं हो गया अब, मैं आपको कॉपी दिलवा देता हूँ ना।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय अनॉथराइज्ड कॉलोनीज में जहां काम हो रहा है वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लैंड ओनिंग एजेंसी हो ही नहीं सकती, वो जमीन तो ग्रामसभा की है या वो ग्रामसभा में वैस्ट हो गई है। नहीं वो लैंड ओनिंग एजेंसी है नहीं कॉर्पोरेशन।

माननीय अध्यक्ष: ये हार्ड कॉपी निकलवाइये, सदन पटल पर रखिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): नहीं वो land owning agency है ही नहीं कॉर्पोरेशन।

माननीय अध्यक्ष: ये हार्ड कॉपी निकलवाईये, सदन पटल पर रखिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं मैं कहता हूँ land owning agency है ही नहीं हो तो...

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी को दे दीजिये एक कॉपी, एक कॉपी बिधूड़ी को दे दीजिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: लैंड तो या तो ग्राम सभा की है या ग्राम सभा में vest हो गई है। कॉर्पोरेशन की लैंड तो है ही नहीं अनॉथराइज़ कॉलोनिज़ में।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: ये एल.जी. साहब को समझाना पड़ेगा।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठिये अब हो गया। माननीय मंत्री जी खड़े हैं दो मिनट बातचीत आपस में नहीं। इसके और कॉपी निकलवा लीजिये ऋतुराज जी।

....व्यवधान....

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: देखिये अध्यक्ष जी जो रेगुलराइज़ कॉलोनी है जो गांव है.

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी बात हो गई मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: काम कर सकती है लेकिन अनॉथराइज़ कॉलोनी में Corporation land owning agency है ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष: चलिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल्ली सरकार है।

माननीय अध्यक्ष: ये आप बोल चुके हैं चलिये बोलिये।

श्री सौरभ भारद्वाज: अब अध्यक्ष जी, अब रामवीर बिधूड़ी जी पुराने नेता हैं दिल्ली के और वो ये सारी चीजें समझते हैं और मुझे खुशी है कि बिधूड़ी जी ने आज इस सदन के सामने सबको ये बताया कि अनॉथराइज़ कॉलोनी की land owning agency एमसीडी नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, अनॉथराइज़ कॉलोनी अलग-अलग तरीके की ज़मीनों के ऊपर कटी हैं, कई जगह वो प्राइवेट ज़मीन थी, कई जगह वो agricultural land थी, कई जगह वो ग्राम सभा की लैंड थी, कई जगह वो एएसआई की थी, कई जगह वो नोरेस्ट की थी तो वो तो अलग-अलग एजेंसिज़ की है या ग्राम सभा में अमेज हो गई थी, ठीक है तो जब उन अनॉथराइज़ कॉलोनी की जो

land owning agency हैं उनको उस अनॉथराइज कॉलोनी की डेव्लपमेंट से कोई लेना-देना ही नहीं है क्योंकि उनकी डेव्लपमेंट वो नहीं कर रहीं हैं, उनकी डेव्लपमेंट दिल्ली सरकार का यू.डी. डिपार्टमेंट फंड देकर फ्लड से या डीएसआईडीसी से करा रहा है तो ये कहना कि अब अनॉथराइज कॉलोनी के लिये एनओसी लगेगा और उसके द्वारा कहलाना एल.जी. साहब के द्वारा जिनका कोई लेना-देना नहीं है अनॉथराइज कॉलोनी से, उनका कोई लेना-देना नहीं है अनॉथराइज कॉलोनी से, उनका कोई लेना-देना, ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है भई, इसके विषय में आपने मीटिंग क्यों बुलाई और उसके विषय में मीटिंग बुलाकर आपने एक ऑर्डर पास कर दिया, मंत्री से आपने पूछा नहीं, मंत्री से आपने बात नहीं की, ये तो गलत है ना और सबसे अच्छी बात है बिधुड़ी जी भी इस बात पर सहमत हैं बिधुड़ी जी कि इस तरीके से जबरदस्ती वो एनओसी की जो ये चीज़ फंसाना और काम रोकना गलत है। एल.जी. साहब को इन सब चीज़ों से बचना चाहिये। उनको तीन काम दिये हैं land, public order aur police वो काम करें थाने-थाने जायें। कभी वो नाले जाते हैं, कभी वो कॉलोनी में जाते हैं, कभी वो टूरिज्म वाले में जाते हैं, कभी वो आर्किलॉजी वाले में जाते हैं। अरे भईया थानों में जाओ ना जहां तुम्हारा काम है, वहां जाओ, रात को वहां पर जाओ। थाने में जो औरतें आती हैं उनकी कम्प्लेंट क्यों नहीं रजिस्टर होती, कत्ल के जो मुकद्दमें आते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन सालों साल क्यों चलती रहती है वो करना चाहिये उनको।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: भई अब ये विषय अब नहीं अब चर्चा नहीं करो, ये चर्चा नहीं है। बस हो गया।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: नहीं अलग से कोई, अलग से कोई नोटिस दीजिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: संजीव जी, संजीव जी हाउस का सेंस है कोई प्रस्ताव, नोटिस तैयार करिये, कल भी हाउस लगेगा कल दीजिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: किसी रूल के तहत तो लेकर आईये ना। राजकुमारी ढिल्लों जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 280 का जो प्रश्न है उससे इम्पोर्टेंट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिये।

माननीय अध्यक्ष: भई मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ बातचीत बंद करें। चर्चा करके ठीक ढंग से रूल के अन्तर्गत लेकर आईये आपस में चर्चा करके।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: अध्यक्ष जी मेरा 280 से ज्यादा मेरा जो महत्वपूर्ण दो मिनटका बस मैं बोलूंगी। विषय है कि अभी सभी

विधायकों ने अनॉथराइज एरिये की बात करी लेकिन मेरा अथॉराइज एरिया रेगुलराइज़ जो एरिया है बहुत कम विधायकों ने बात रखी। उसमें जो एमसीडी है land owning agency, flood and irrigation को वहां पर।

माननीय अध्यक्ष: भई राजकुमारी ढिल्लों जी आपका ये विषय नहीं है विषय दूसरा है।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: सर मेरा छोटा सा मेरा उससे इम्पोर्टेंट ज्यादा है ये।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब इसी पर आईये समय नहीं है प्लीज़। उस पर चर्चा हो गई वहां।

श्रीमती राजकुमार ढिल्लों: ओके थैंक्यू।

माननीय अध्यक्ष: बाद में होगी दोबारा।

श्रीमती राजकुमार ढिल्लों: माननीय अध्यक्ष जी 280 के माध्यम से मैं मेरी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण विषय रखना मैं चाहती हूं कि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, परिवहन व्यवस्था पर और परिवहन व्यवस्था को दिल्ली में मज़बूत करने के लिये दिल्ली को प्रदुषण मुक्त करने के लिये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बहुत तेज़ी से सुदृढ़ किया जा रहा है जिसमें कि दिल्ली की महिलायें मुफ्त सफ़र करती हैं, बुजुर्ग जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरी विधानसभा में

दिवकत चल रही है कि परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी है लेकिन जो हमारे बस स्टापेज हैं, बस स्टैंड हैं उनके ऊपर शैल्टर नहीं है, सिर्फ एक बस स्टैंड के नम्बर लिखे हुये हैं उसके ऊपर और कई बार मेरा लिखित मैंने अपना रिक्वेस्ट भी मैंने भेजी है डिपार्टमेंट में और परिवहन मंत्री साहब को भी मैंने भेजी है तो आज इस सदन के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बुजुर्गों के लिये, बुजुर्ग महिलाओं के लिये, हैंडीकैप लोगों के लिये ये जो आगे गर्मी आयेगी, कड़कती धूप, कड़कती सर्दी और बरसात के दिनों में हमें अपने शैल्टर को हमें बनवाना होगा। तो परिवहन मंत्री से मेरा निवेदन है कि मैंने डेढ़ दो साल पहले मेरी विधानसभा के नौ बस स्टैंड जो की खत्म हो चुके हैं बिल्कुल वहां नज़र ही नहीं आते, लोग खड़े होते हैं उसके लिये कोई ना कोई रास्ता निकलवायें और उसको तुरंत प्रभाव से बनवायें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सोमनाथ भारती जी। बहुत संक्षेप में सोमनाथ जी विषय आ गया ये।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र के अंदर डीटीसी बस स्टैंड, मैं काफी समय से विभाग के सामने ये बात उठा रहा हूँ माननीय मंत्री जी हँस रहे हैं, तो ये कई सारे बस स्टैंड ऐसे हैं जिस पर जोकि बैठने लायक भी नहीं हैं और दो स्पेशली चूँकि वो जो डीएलए माल है साकेत में उसके अपोजिट में काफी समय से बस स्टैंड्स की मांग कर रहे हैं वहां की जनता खिड़की विलेज की और उसको हमने विभाग के सामने कई बार रखा लेकिन वो

पता नहीं क्या चल रहा है, किसके अधीन वो काम कर रहे हैं, किसका कहना मान रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है माननीय मंत्री जी से कि आज इस बात का संज्ञान लें कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी डीटीसी के बस स्टैंस हैं सबका एक बार लेखा-जोखा मंगवा लें और जो रिक्वेस्ट पैडिंग है खिड़की गांव के दो बस स्टैंड के रिक्वेस्ट पैडिंग है वहां पर दो-चार एक्सडेंट्स भी हो गये हैं इस चक्कर में, मैं चाहता हूं कि आप इसका संज्ञान लेकर के और इन बस स्टैंड्स का लेखा-जोखा मंगवायें और जहां-जहां जरूरत है इम्प्रूवमेंट की उसका आदेश दें आपका धन्यवाद, तो वो मैं रख लूं जो बताया था।

माननीय अध्यक्ष: नहीं वो हो गया हो गया।

श्री सोमनाथ भारती: धन्यवाद प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारती: वो रख लें उनके....

माननीय अध्यक्ष: रखिये, रखिये, जल्दी रखिये, कम शब्दों में रखिये।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही मार्मिक बात आपके समक्ष और आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 30 जूलाई, 2023 को मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लेबर चौथी मंजिल से गिरकर उनका देहांत हो गया। उसके एक सप्ताह बाद ही

उनकी बेटी की शादी भी थी, मैं वहां रात को पहुंचा तो देखा कि बहुत ही दुर्दशा हो गई थी उनकी भी। तो ये बात मैं इसलिये ला रहा हूं क्योंकि आज उनका परिवार भी आया हुआ है सदन में। ये बात जब मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास लेकर पहुंचा कि उस लेबर का परिवार उनके पास कोई सोर्स ऑफ इन्कम नहीं और पांच-पांच बेटियां हैं और बिहार के रहने वाले हैं मूलतः, दिल्ली में इस वक्त अपने काम को लेकर के रह रहे थे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उनकी। आपको हैरानी होगी एक सैकेंड नहीं लगाया माननीय मुख्यमंत्री ने और तुरंत ही मुझे कहा कि भई जाकर के कन्सर्न्डडी.एम. से मिलो और मैं आदेश दे रहा हूं। तो आज साथियों को बताते हुये मुझे गर्व हो रहा अपने मुख्यमंत्री पर कि 10 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर उस गरीब की पत्नी को मिला जो आज यहां बैठी हुई है।

माननीय अध्यक्ष: चलिये सोमनाथ जी बैठिये।

श्री सोमनाथ भारती: ये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं और एक बात और कहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: हो गया सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: एक सैकेंड, एक सैकेंड।

माननीय अध्यक्ष: समय नहीं है प्लीज़।

श्री सोमनाथ भारती: एक सैकेंड बस एक लाइन। भाजपा, कांग्रेस कहती है की हम जनता के लिये काम करते हैं लेकिन जब उस गरीब

का देहांत हुआ ना तो वहां ना भाजपा पहुंची ना कांग्रेस पहुंची, पहुंची तो आम आदमी पार्टी पहुंची, आम आदमी पार्टी का विधायक पहुंचा और भाजपा, कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है जनता से कुछ लेना-देना नहीं है अध्यक्ष महोदय, गरीबों का मसीहा अगर कोई है इस देश के अंदर वो अरविंद केजरीवाल है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारती: धन्यवाद, श्री अजय दत्त जी, बहुत संक्षेप में जो लिखा है वो ही पढ़ियेगा समय नहीं है।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं आपने मुझे एक गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी पिछले हफ्ते मुझे मेरे घर के एक नम्बर पर एक threat call आया जिसमें मेरे मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी गई और ये threat call पहले भी आये। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई फर्जी कॉल हो लेकिन जब पिछले हफ्ते ये कॉल आया तो उसमें मेरे बच्चों का नाम और कुछ ऐसी डिटेल उन्होंने बोलकर कहा कि भई तुमको गाली देकर के तुमको मार दिया जायेगा और ये कर दिया जायेगा वो कर दिया जायेगा, मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और इस पर मैंने पुलिस कमिशनर साहब को चिट्ठी लिखी पांच दिन पहले 17 तारीख को चिट्ठी रिसीव करवा दी अध्यक्ष जी। डीसीपी साउथ को चिट्ठी लिखी उनको रिसीव करवा दी और थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी वहां से रिसीव करवा दी। स्पेशल सैल को चिट्ठी लिखी उनको सबको रिसीव करा दी और अभी तक किसी ने भी दिल्ली पुलिस से मेरे पास कॉन्टेक्ट तक नहीं किया, ना कोई पूछताछ की, ना

अभी तक कोई रिस्पोंस है कि भई वो जो threat call थी मैंने बकायदा इसमें वो नम्बर लिखा हुआ है और उस threat call से क्योंकि मेरी वाइ भी उस समय मेरे साथ थी वो सब घबरा गये क्योंकि जब बच्चों का नाम लेकर इस तरह की threat call हम लोगों को आ रही हैं तो दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं और पांच दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जब इन्हें मौका दिया, मैंने कहा भई मैं अपनी शिकायत लिखित में दे रहा हूँ उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल मैंने ये बात आपके साथ सांझा की और फिर मैं इस सदन पटल पर ला रहा हूँ कि दिल्ली के चुने हुये विधायकों को जब इस तरीके की कॉल आती हैं और उनके बच्चों तक के नाम से कॉलें आती हैं उस पर दिल्ली पुलिस क्यों संज्ञान नहीं ले रही है और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहां दिन-रात लड़ाई-झगड़े, मैं आपको इस सदन में पहले भी बता चुका हूँ, मेरे ऑफिस के बिल्कुल बाहर दो-दो मर्डर हुये हैं, आये दिन चाकू-छुरी मर्डर के केस होते रहते हैं तो अध्यक्ष जी।

....व्यवधान....

श्री रोहित कुमार: मेरे घर के बाहर भी सौ मीटर के दायरे में एक साल में दो-दो मर्डर हो गये हैं।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी मैं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है मुझे।

माननीय अध्यक्ष: अजय दत्त जी ये supporting document सदन के पटल पर रख दीजिये।

श्री अजय दत्त: जी।

माननीय अध्यक्ष: जो आपके पास supporting documents हैं जो-जो.

श्री अजय दत्त: नहीं, मैंने जो उनको कम्प्लेंट दी है ये में इनको दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: इसकी कॉपियां जब-जब आपने लिखी हैं।

श्री अजय दत्त: जी जी।

माननीय अध्यक्ष: रिमाइन्डर लिखा है वो सदन पटल पर दे दीजिये।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी मेरा ये कहना है कि अगर हम जैसे विधायकों के साथ भई आपने कम से कम ये पूछा होता कि क्या पूरा केस हुआ है, क्या बात हुई है, उस पर कुछ सर्तकता आप लें, समझ में आता है कि दिल्ली पुलिस, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस लैवल पर जा रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड देने से क्या ऐसी threat रूक जायेंगी और इससे पहले भी ये मैंने दोनों चीजें इसमें पूरा लिखा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: चलिये अब, हो गया।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर विषय है और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि दिल्ली पुलिस कमिशनर साहब को ये बतायें और पूछें कि क्यों आप ऐसे गंभीर विषय पर इमिडेट संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों दिल्ली के चुने हुये विधायक और दिल्ली की जनता के साथ सुरक्षा में आप क्यों कोताही बरत रहे हैं? मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने मुझे एक गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ मैं मेरे क्षेत्र के अंदर भी जो है आये दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, आये दिन वारदात होती जा रही हैं, उन पर भी लगाम लगे और दिल्ली के हर एक नागरिक को सुरक्षा का आभास हो ऐसी व्यवस्था दिल्ली पुलिस करे, ऐसी व्यवस्था एल.जी. साहब करें क्योंकि यही काम एल.जी. साहब को दिया गया है, धन्यवाद अध्यक्ष जी, जय भारत, जय भीम।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेंद्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, आपने गंभीर समस्या पर बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक पांच बीघे ज़मीन है जिसमें कुछ भू-माफिओं ने नर्सरी बनाकर उसमें नर्सरी चला रहे हैं। इस संबंध में मैंने कई बार डीएम, एसडीएम से भी बातचीत की और शिकायत भी की कि भू-माफियों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुये नर्सरी को यहां से हटाया जाये। माननीय अध्यक्ष जी हद तो तब हो गई जब उस भू-माफिया ने

वहां पर एक अस्थाई मकान भी बना लिया है। मकान में बिजली का कनेक्शन भी करवा लिया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ये संज्ञान में लेते हुये, नर्सरी के भू-माफिया पर सख्त कार्रवाई करते हुये इस भूमि को जल्द से जल्द खाली कराया जाये जिससे भूमि का प्रयोग करके यहां पर आधुनिक स्कूल बनाया जाये एवं दिल्ली सरकार शिक्षा मॉडल लागू किया जा सके क्योंकि यहां ज़मीन दिल्ली सरकार की है और ये ज़मीन दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देश में एक मॉडल स्कूल बनाया जाये इसी संबंध में आपसे शीघ्रातिशीघ्र संबंधित डीएम, एसडीएम को दिशा निर्देश करें तथा इस ज़मीन को तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाये, ये ज़मीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबोली के पास है, टीले के पास लगती है ये मंडोली की स्कूल है कि जगह आप इसको यदि आदेश करेंगे तो आपका धन्यवाद होगा।

माननीय अध्यक्ष: अल्पकालिक चर्चा नियम-55

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: तो उसी में उसी में जब चर्चा होगी मैं आपको दूंगा समय। चर्चा होगी ना समय दूंगा।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: चलिये पढ़िये। भई महेंद्र जी, अब ऐसे नहीं समय।

श्री राजेंद्रपाल गौतम: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ 280 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। Delhi SC/ST/OBC Minority, Handicap Development Finance Corporation जो 1983 में बना था जिसके 49 परसेंट शेयर भारत सरकार के थे और 51 परसेंट शेयर दिल्ली सरकार के थे जिसमें भारत सरकार ने 50 परसेंट जो देना था 49 परसेंट उसमें से केवल 11.88 करोड़ दिल्ली सरकार को दिया और दिल्ली सरकार ने जो 38.32 करोड़ रुपया दिया जबकि भारत सरकार की तरफ अभी 38 करोड़ 12 लाख रुपये बकाया है और दिल्ली सरकार की तरफ 11 करोड़ 38 लाख रुपये बकाया है। उक्त निगम का शेयर 98 परसेंट उप-राज्यपाल जी के पास है एक परसेंट सचिव एससी/एसटी के पास है और एक परसेंट डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर Schedule Caste Component Plan उसके पास है। यह निगम no profit पर कार्य करता है यह निगम भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार के माध्यम से Delhi SCè STè OBC Minority, Handicap Development Finance Corporation में 90 परसेंट आबादी को कवर करता है जो रिहायशी दरों पर ऋण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। DSFDC में वर्तमान में 131 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं जिनको वर्ष 1996-97 से कोई ग्रांट इन एड प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण दिल्ली के अधिकारियों की उदासीनता एवं गैर रवैये के अनुसार कोई राशि प्राप्त ना होने के कारण सभी अधिकारी व कर्मचारी पिछले पांच-छः महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है और ना ही कोई लोन जनता को मिल रहा है जो अपना स्व-रोजगार कर सकें इसके कारण

निगम के कर्मचारियों की हालत काफी दयनीय है। निगम के कर्मचारी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई जबकि एक अनुसूचित जाति का अधिकारी 31.01.2024 को सरकारी विभाग के कार्यालय में उसने सुसाइड कर लिया, उसकी डेथ हो गई और एक कर्मचारी को पहला जो अटैक आया, उक्त विभाग में वेतन के साथ चिकित्सा भत्ते इत्यादि बंद हैं इसके अतिरिक्त ये कहना कि निगम का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था उससे पिछड़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब इसके 98 परसेंट शेयर उप-राज्यपाल जी के पास हैं तो मैं माननीय उप-राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि ग्रांट-इन-ऐड देकर इस विभाग को चलायें, और, और कहीं से फंड हमें मांगने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान फंड का पैसा है एससी/एसटी का है उसमें से ही दे दें। कहीं और से फंड की जरूरत नहीं है और अगर आप चाहते हैं इसको बंद करना तो भई अब वो स्पष्ट कर दें। उप-राज्यपाल कम से कम बतायें तो सही। जिन अधिकारियों के माध्यम से इस विभाग को फेल किया जा रहा है। लोगों को ऋण मिल जाया करते थे, सस्ते दर पर वो अपना रोजगार कर लेते थे। SC/ST/OBC/Minority/Handicap Development Finance Corporation जो 90 परसेंट से ज्यादा को कवर करता है अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष: बस हो गया अब हो गया।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम: उनकी हालत बहुत खराब है। एक और तर्क सिर्फ वो दे रहे हैं कि इसमें अधिकारी कर्मचारी ज्यादा हैं। तो मैं कहता हूं पहले एक विभाग था जो बैट्री बस चलाया करता था आज

से 40 साल पहले वो बैट्री बस के विभाग को बंद किया गया और उनके कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने absorb कर लिया। अगर कुछ फालतू है तो दिल्ली सरकार में कर्मचारियों की कमी है, peons की कमी है, वहां से लेकर उनको absorb कर लें। लेकिन इस समस्या का समाधान कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा। श्री कुलदीप कुमार जी, चण्डीगढ़ के मेयर चुनाव में कथित हेराफेरी से लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के प्रयास और इसके विरुद्ध माननीय...

....व्यवधान....

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री कुलदीप कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम 55 के तहत चण्डीगढ़ मेयर चुनाव के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने का मुझे मौका दिया और एक शायरी कह कर अपनी बात शुरू करूंगा -

“ये रूतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया,

ये सम्मान मुझे तेरे संविधान ने दिया,

औरों को जो मिला होगा मुक्कदर से मिला होगा,

हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला।”

अध्यक्ष महोदय, कल पूरे देश ने देखा कि जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चण्डीगढ़ मेयर चुनाव जिसके अंदर इतनी बड़ी

धांधलेबाजी की गई थी, सब लोगों ने देखा कि कैसे असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, इस चुनाव को किस प्रकार से ये कहते हैं ना बूथ कैपचरिंग वोटों की चोरी, किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चण्डीगढ़ में करने का काम किया और पूरे देश ने देखा, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि अध्यक्ष जी अगर जब वहां पर वोट डल रहे थे, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे और मात्र 16 वोट जो थे वो बीजेपी के पास थे। लेकिन देश ने देखा कि कैसे 20 वोट वाली पार्टी को हरा दिया गया और 16 वोट वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। ये कैसे हुआ, ऐसा कौन सा फार्मूला लगाया कि जो ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर बनाया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी का माईनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था, जिसको केवल इस लिए बनाया गया था कि वो उस चुनाव में धांधली कर सके और कैसे 20 वोट वाली पार्टी को हरा सके और 16 वोट वाली पार्टी को जिता सके। उसने क्या किया, उसने 8 के 8 वोट कैसल कर दिये और जब वो वोट कैसल किये गए वो तो अच्छा हुआ कि वहां जो विपक्ष के पार्षद थे उन सबने मांग रखी थी कि जब प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर जब वोट डलें तो ऊपर एक कैमरा होना चाहिए। सोचिये अगर वो कैमरा वहां पर नहीं होता, अगर वो कैमरा वहां नहीं लगा होता तो हम आम आदमी पार्टी वाले सब कहते रहते वोटों की चोरी हो गई और भाजपा वाले कहते सबूत दो, सबूत दो, क्या चोरी हुई है, ये कहते रहते और हम से सबूत मांगते रहते और बड़े साफ-सुथरे बने रहते। लेकिन क्या

हुआ, वो वारदात जब कैमरे में कैद हुई और सर्वोच्च न्यायालय में गए, हम लोग हटे नहीं, हम लोग डटे रहे और डटे रहकर क्योंकि हमें पता था कि हमारा एक-एक वोट जो गया है वो एक-एक व्यक्ति का वोट आम आदमी पार्टी के मेयर को गया है। हम सबको ये बात पता थी स्पष्ट रूप से। इसलिए हम डटे रहे और सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो फैसला दिया उसने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करने वाली पार्टी है। ये बात सबके सामने खुले आम हो गई। ये सबको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया के चुनाव लड़ कैसे रही है। आज वो चुनाव लड़ रही है ईडी के दम पर, आज वो चुनाव लड़ रही है सीबीआई के दम पर और ईडी और सीबीआई के साथ-साथ वैलेट पेपर में भी जुगाड़ किया जा रहा है। ईवीएम भी जुगाड़ किया जा रहा है। सारे हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। उन हथकंडों के बावजूद वो किस प्रकार चुनाव लड़ने का काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के सामने अध्यक्ष जी ये बात आज स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी की है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो इस देश से..

माननीय अध्यक्ष: कन्क्लूड करिये कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमार: वो इस देश से लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी एक बात और कहना चाहता हूं सबके लिए जब हम वोट चुनाव लड़ने जाते हैं तो सबके लिए कहा

जाता है कि जी 25 लाख रुपये की सीमा है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि इस देश के संविधान में इस देश के इलैक्शन कमिशन को पता है कि अगर यहां अपनी मर्जी से पैसा खर्च किया जाएगा, सब कुछ किया जायेगा तो पैसे वाले लोग चुनाव जीतते जायेंगे। गरीब तबके के व्यक्ति को, गरीब आदमी को राजनीति में आने का लोक सभा में, विधान सभा में आने का समान अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आज जिस ढंग से..

माननीय अध्यक्ष: कुलदीप जी कन्क्लूड करिये प्लीज। नहीं कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री कुलदीप कुमार: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। आज जिस ढंग से किया जा रहा है, चुनावों को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन मैं इन विषम परिस्थितियों के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों के अंदर जो फैसला दिया है, मुझे लगता है इस देश के अंदर एक नई उम्मीद एक नई ऊर्जा दोबारा शुरूआत हुई है और सब देश के लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती के साथ अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं और मैं आज धन्यवाद करता हूं और जो हमारे मेयर जीते हैं कुलदीप कुमार जी चण्डीगढ़ से मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक बात और कहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं। एक शायरी कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष जी:

“नभ में तारे बहुत हैं, अनेक है
लेकिन दुनिया एक चांद को निहारती है,

नभ में तारे बहुत हैं अनेक है
लेकिन दुनिया एक चांद को निहारती है,

आवाज से प्रखर, मन से निर्भीक दुनिया उन्हें
अरविंद केजरीवाल के नाम से जानती है।”

अरविन्द केजरीवाल जी, इन तमाम बाधाओं के बाद भी डटे हुए हैं और देश देख रहा है कि अरविन्द केजरीवाल जी कैसे इन तानाशाहियों का आज किस तरह से सामना करने का काम कर रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष: जिन-जिन सदस्यों को मैं बोलने के लिए बोलता हूँ वो कृपया पांच मिनट का समय लें, इससे ज्यादा ना लें। श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज इस देश के eminent jurist और personal expert Fali Sam Nariman का निधन हुआ है। मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और Fali Sam Nariman साहब की बात से शुरू करता हूँ। वो कहते थे कि 'constitution how successfully it function depend largely on how person in power work them and how person authority interpret them.' मुझे ये लगता है कि how person in power किस तरह से पूरी संस्था का मिस्यूज कर रहे हैं वो पूरा देश

देख रहा है। लेकिन how person authority means judiciary और जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस संस्था को बचाने की कल एक ऐतिहासिक काम किया है, मैं पूरे सदन और पूरे देश के 140 करोड़ जनता की तरफ से मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब constituent assembly का फाइनल ड्राफ्ट हो रहा था। फाइनल ड्राफ्ट में adoption के समय 25 नवम्बर, 1949 को बाबा साहेब ने ये कहा था कि 'I shall not enter into the merit of the constitution because I feel however good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad because those who are called to work it, happen to be bad lot. However, a bad constitution may be it may turn out to be good, if those who are called to work it happen to be a good. So the working of the constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution.' मैं आज पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अगर आजादी के बाद आ गई होती तो इस देश में आज ना जनतंत्र बचता, ना संविधान बचता क्योंकि जिस तरह से रोज संविधान की हत्या करने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है ये दर्शाता है ना तो उनको संविधान में भरोसा है ना इस देश के जनतंत्र में भरोसा है। चूंकि जैसा हमारे साथी कुलदीप भाई कह रहे थे आंकड़ा तो बिल्कुल साफ था ना कि 20 वोट इंडिया अलायंस के पास था, 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास था। अगर 20 वोट इंडिया अलायंस के पास है, 16 वोट बीजेपी के पास है तो कोई भी आदमी कहेगा जब वोट होगा तो इंडिया अलायंस कैन्डीडेट

जीतेगें और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता था। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपना प्रत्याशी खड़ा किया तो उसका मंशा क्या रहा होगा। मंशा तो ये ही रहा होगा ना कि मैं 16 हूं वो 20 हैं हम चार तोड़ लेंगे या तीन तोड़ लेंगे और हमारी सरकार बन जायेगी। हमारा मेयर बन जायेगा। तो उनका intention तो पहले से horse trading करके अपनी मेयर बनाने का था। तो जब लोग कह रहे हैं कि ये प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर की गलती थी, प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर की गलती नहीं थी, ये पूरा वेल-प्लान्ड भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ सभी नेताओं का था और कोशिश कब शुरू हुई। अब देखिये पहला वोट 18 फरवरी को होना था। 18 फरवरी तक इन्होंने देखा कि हमारा इनका पार्षद नहीं टूट पा रहा है। तो जो प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर था उसने कहा कि जी मैं बीमार हो गया हूं और कहा अब डेट 5 मार्च का होगा क्योंकि उनको लगा कि इस बीच में हम अपना वोट तोड़ लेंगे। हमारे लोग वहां पर जो पैटीशनर थे कुलदीप कुमार जी वो मेयर का प्रत्याशी थे वो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने डेट तय किया 30 तारीख का। अब 30 तारीख तक ये horse trading करके पार्षदों को नहीं तोड़ पाये, तो जब पार्षदों को नहीं तोड़ पाये तो 30 तारीख को फिर जो वहां पर हुआ उसको पूरे देश ने लाइव देखा और सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब आप वो वीडियो आप लोग थोड़ा entertainment भी मिलेगा आपको उसमें। मुझे ये लगता है कि आज वोट की चोरी होती है भारतीय जनता पार्टी करती है। वोटों की गड़बड़ी करती है, ये पूरा देश कहता है लेकिन आज तक सबूत नहीं था। तो कई बार होता है

ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर वाला कई बार जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है। तो 30 तारीख को उस दिन भी कोशिश खूब किया जब पूरा विडियो देखेंगे एक-एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी को पता था कि कैमरे कहां लगा हुआ है। वो कहा कि कैमरे घुमा दो, कैमरे घुमा दो, कैमरे घुमा दो। लेकिन भगवान को कहना था कि तुम्हारे पाप को भी एक्सपोज करेंगे। वो कैमरा नहीं घूम पाया और जब वो कैमरा नहीं घूम पाया। ऊपर वाले ने उन पर उनका जो पाप है उनके पाप को एक्सपोज करना था, तो वोटों की चोरी लाइव पकड़ी गई। जब वोटों की चोरी लाइव पकड़ी गई फिर उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। इंडिया अलायंस के लोग हाई कोर्ट गए। हालांकि हाई कोर्ट में स्टे मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। अब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुझे ये लगता है कि एक लैंड मार्क डिसिजन जब कभी भी इसकी चर्चा होगी तो ये देश देखेगा। सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल संविधान में जो है उसका उपयोग किया और 142 सैक्शन article 142 का जो है वो कहता है कि 'it vests Supreme Court to the re-projectory of discretionary power that can be viewed in appropriate circumstances to deliver complete justice in a given case.' चूंकि कई लोग ये कहते हैं कि भई अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। मुझे ये लगता है कि 1993 में Fali Sam Nariman साहब ने ही एक केस था Supreme Court advocate on record Association Vs. India 1993 जिसको रिप्रजेंट

Fali Sam Nariman साहब ही कर रहे थे। एक लैंड मार्क डिसिजन हुआ वो 09 बेंच का जज था 7/2 का फैसला, उसी में उन्होंने कहा था कि 'in a democratic polity, the supreme power of the state is shared among the three principles organ that is, constitutional functionaries namely, the Legislature, the Executive and the Judiciary. Each of the functionaries is independent and supreme within its allotted sphere and none is superior to other.' और फिर उन्होंने कहा 'Indeed it is the role of the judiciary in carrying out the constitutional message and its responsibility to keep vigilant watch over the functioning of democracy in accordance to the dictate, directives and imperative command of the constitution by checking excessive authority of the constitutional functionaries beyond the cane of the constitution.' हम ये मानते हैं।

माननीय अध्यक्ष: संजीव जी अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री संजीव झा: बस तीन ही बात मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि अगर democratic functionaries अपनी जिम्मेदारी को संविधान संवत् निर्वाह नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट watch dog का काम करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात को किया। तो इससे तीन बातें तय होती हैं। एक बात और ये पूरे देश की जनता को कहना भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल 36 वोट का था, आंकड़ा 36 का था और 36 के आंकड़े में प्रधान मंत्री जी फंस गए इस बार कि 36 के आंकड़े में प्रधान मंत्री

जी ने आठ वोट की चोरी करवाई। यानि 25 परसेंट वोट की चोरी करवाई जो कल माननीय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। तो जब बात 90 करोड़ की वोट की है और जिसमें प्रधान मंत्री जी को चुना जायेगा सोचिये प्रधान मंत्री जी क्या-क्या करते होंगे और कुछ instance तो सामने हैं जो चुनाव में दिखता है कि पहला जहां कहीं भी ये लगता है कि यहां दूसरी पार्टी का वोट को, पहले वोट को कटवाया जाता है, फिर उसके बाद लगता है नहीं वोट के दिन लगता है कि नहीं वहां इस पार्टी का वोट है, वहां ईवीएम खराब करवाया जाता है और उसके बाद उनको लगता है कि उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर तीसरे तरीके की चोरी होती है जिसकी चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज इस देश का जनतंत्र जिसको इस देश की जनता ने अपनी सरकार को चुना था। लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार अलौकतात्रिक काम कर रही है। तो अगर अलौकतात्रिक काम कर रही है तो फिर इस देश का संविधान इस देश का जनतंत्र सुरक्षित नहीं है और जब इस देश का जनतंत्र सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले इस देश की जनतंत्र को इस देश के संवैधानिक मर्यादा को सुरक्षित रखें। चूंकि ये चुनाव तभी होगा, सरकार तभी चुनी जायेगी जब इस देश का जनतंत्र मजबूत होगा। तो मुझे लगता लड़ाई बहुत बड़ी है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली और देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि दो ढाई महीने बाद फिर चुनाव होने है। इस तरह से अगर सरकार को आप निरंकुश बना देंगे तो ना देश का संविधान

बचेगा, ना इस देश का जनतंत्र बचेगा। चण्डीगढ़ का चुनाव आपके सामने है। तो आज मुझे उम्मीद है कि जब-जब इस देश के जनतंत्र पर कुठाराघात करने की कोशिश की गई है इस देश की जनता ने उस तमाम सरकारों को माकूल जवाब दिया है और ढाई महीने बाद भी जवाब मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ आज मैं फिर से अपनी बात खत्म करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए शल्यूट और धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस निर्णय ने उन तमाम लोगों को जिनको इस सरकार पर भरोसा नहीं था। सरकार की जो मशीनरी है उस पर भरोसा नहीं था, उसके मन में सांत्वना मिला है कि अगर अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट और ज्यूडिशरी खड़ा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी, सीमा के साथ। प्लीज समय की सीमा है। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: केवल पांच मिनट सोमनाथ जी, प्लीज। मेरी सीमाओं को समझिये।

श्री सोमनाथ भारती: मैं बैठ सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं पांच मिनट में बोल सकते हैं। बहुत कुछ हैं पांच मिनट। आप बोलिये।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, जो ये मेरे साथियों ने वक्तव्य रखा है अभी कल के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के ऊपर, बहुत ही चिन्ता-जनक बात है ये जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश के सामने एक्सपोज किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली को और देश को बताना चाहूंगा, इस फ्रॉड का जेनेसिस इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मेशन है आप सोचें जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भई इलेक्शन कमीशन को सलैक्ट करने के लिए एक तो माननीय प्रधानमंत्री हो जाएं एक सीजेआई हो जाए, एक एलओपी हो जाए। आप इनके दुस्साहस देखें भाजपा का, भाजपा ने क्या किया कहता है नहीं-नहीं सीजेआई को हटा कर के प्रधानमंत्री मनोनीत मंत्री को डाल दिया। तो एक प्रधानमंत्री हो गए एक उनके मनोनीत मंत्री हो गए, एक एलओपी हो गए तो ये कोई रॉकेट साईंस नहीं है कि फिर इलेक्शन कमीशन नहीं होगा वो भाजपा इलेक्शन कमीशन होगा। इस पूरे फ्रॉड का जेनेसिस वहां है। अध्यक्ष महोदय, आज देश पूछना चाहता है एक तरफ एक शख्स है अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में अनेकों काम करके जनता का दिल जीता। एक के बाद एक चुनाव दिल्ली की जनता ने जिताये। पंजाब जिताया, गोवा में एमएलए दिए, गुजरात में एमएलए दिए। एक तरफ इस शख्स ने पूरे देश के आगे काम की राजनीति के बल पर डेमोक्रेसी के अंदर अपना नाम दर्ज कराया। एक पॉपुलर लीडर, पॉपुलर पार्टी के नाम पर हमारा नाम दर्ज हुआ है काम के बल पर। दूसरी तरफ जिस प्रकार की हरकतें भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू

कर दिया है इससे पूरे देश का नाम बदनाम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना घटी है, कल जो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर हुआ है उससे एक बात तो सिद्ध हो गया जो हर तरफ निराशा का माहौल हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता तो जो कल का जजमेंट आया है कल का जो ऑर्डर आया है उसमें बाकी सब तो ठीक है लेकिन इस मसीह का मसीहा कौन है जब तक बात वहां नहीं पहुंचेगी तब तक इस पर न्याय नहीं आएगा। ये जो अनिल मसीह है इसकी अपनी औकात नहीं है, इसका अपना हिम्मत नहीं है इस प्रकार की हरकत करने का। इस मसीह का मसीहा कौन है इस पर भी जांच होनी चाहिए इस पर पता लगना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आप देखें किस प्रकार से इन्होंने खुले आम गुंडा गर्दी, डकैती करी है जनता के मत की डकैती करी है। जनवरी 18 को जब ये सुनिश्चित हुआ कि भई चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होगा तो पहली गलती और पहला फ्रॉड कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को बनाया आपका पोलिंग ऑफिसर, ये पहला फ्रॉड है, दूसरा फ्रॉड वो व्यक्ति कहता है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसकी रीढ़ की हड्डी में वाकई में दर्द था? रीढ़ की हड्डी पता नहीं थी, नहीं थी देश को सिद्ध हो गया और उसने कहा फरवरी 6 को होगा चूंकि मेरी तबीयत खराब है। तो जो हमारे पार्षद वहां कम थे चंडीगढ़ के अंदर वो हाईकोर्ट गए, हाई कोर्ट पर 23 तारीख को मैटर लगा 24 तारीख को आर्डर आया कि जनवरी 30 को चुनाव करा दो। अब चुनाव जब कराते हैं तो वहां हिम्मत देखिए मतलब मैं तो सिहर उठता हूं इस बात को सोच के

कि जब ये कैमरे के ऑब्जरवेशन में, कैमरे के मॉनिटरिंग में इस प्रकार गलत कर सकते हैं तो पता नहीं क्या करते होंगे पीछे, जहां ना माइक्रोफोन है, जब वोट डलता है तो इसके अंदर ना कोई वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो इस प्रकार से, तो ये जो कल की हरकत है और बड़ा दुस्साहस इतना दुस्साहस कि वो व्यक्ति जब पांच फरवरी को मैटर लगा माननीय उच्चतम न्यायालय के पास और जब नोटिस इश्यू हुआ और जब उसको बुलाया गया 19 तारीख को उसके बीच देखो क्या घटना घटी, इनको लगा कि भई सुप्रीम कोर्ट तो नेचुरल सी बात है इसको set aside करेगी जो कि मामला सारा कैप्चर हो चुका है, तो बीच में तीन पार्षदों को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों को अगवा करके पता नहीं उनको पैसे के लालच दी, उनको सीबीआई का डर दिया, उनको ईडी का डर दिया, क्या करा तीन पार्षदों को अपनी तरफ करने का प्रयत्न किया। सबने देखा और ये बात उच्चतम न्यायालय ने बाकायदा अपने ऑब्जर्वेशन में कहा 19 फरवरी को, कहा कि हम भी देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में horse trading हो रहा है। ये बात कही और जब कहा कि भई अनिल मसीह जब वहां पर पहुंचे उनको पूछा कि भई ये बताएं क्या आपने defacement करी थी वो तो बकायदा conversation हर तरफ घूम रहा है, हां जी करी थी, क्या आपने मार्क करा था-हांजी करा था। आपने कितनों में करा था-आठ में करा था। हिम्मत देखिए मतलब कोर्ट नंबर-1, उससे बड़ा कोर्ट नहीं है देश में, सीजेआई के सामने वो व्यक्ति एडमिट कर रहा है कि हमने करा था, क्यों करा था, कहता है defacement था पहले जिसको मार्क करके

अलग कर रहे थे। उस वक्त जब सीजेआई ने कहा कि वो आठों के आठों जो बैलेट पेपर है मेरे सामने लेकर के आइए और बीस तारीख को वो सारे बैलेट पेपर प्रोड्यूस किए गए।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिए सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: बस लास्ट पार्टी। उस वक्त एक बात और देखने लायक थी मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है भाजपा में। भाजपा के जो वकील थे ऑफकोर्स वकील वही बोलता है जो क्लार्क चाहता है। तो क्लार्क ने कहा अपने वकीलों को भई ये बोलो कि इन्होंने मांगा है कि फिर से चुनाव करा दीजिए, क्यों करा दीजिए, क्योंकि हमने तीन खरीद लिए हैं, तीन खरीद लिए हैं तो इस बार हम फिर जीत जाएंगे। तो इनको बेसिकली मुसीबत क्या है कि माननीय मोदी जी चाहते नहीं हैं। मैं अखबार में आज देख रहा था अखबारों में कहीं नहीं लिखा, किसी का हिम्मत नहीं हुआ लिखने का कि INDIA alliance ने भाजपा को हराया, किसी ने नहीं लिखा। लोगों ने लिखा कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराया तो INDIA alliance भाजपा को हरायेगा अखबार लिखे ना लिखे, टीवी बात करे ना करे लेकिन 2024 में INDIA alliance भाजपा को हरायेगा।

माननीय अध्यक्ष: चलिए सोमनाथ जी अब हो गया।

श्री सोमनाथ भारती: और दूसरी बात।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी अब नहीं कंकल्यूड करिए।

श्री सोमनाथ भारती: एक लास्ट, मैं उन अधिकारियों को बताना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: भाई साहब अब औरों ने भी बोलना है।

श्री सोमनाथ भारती: भाजपा के कहे अगर गलत करोगे तो जो अनिल मसीह के साथ होगा अब 340 सीआरपीसी के तहत उस पर मुकदमा चलेगा वो जेल जायेगा, तो अब सभी ध्यान कर लें भाजपा माना आज brutal force में है लेकिन brutal force में अगर आपने भाजपा के कहे गलती किया तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अनिल मसीह के साथ किया है वही आपके साथ होगा, इसलिए संविधान की इज्जत करना सीखें। डेमोक्रेसी की इज्जत करना सीखें और लाइन को क्रॉस ना करें। सच के साथ रहें, झूठ का साथ ना दें।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री सोमनाथ भारती: आज भाजपा झूठ का पुलिंदा बन चुकी है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश गुप्ता: अध्यक्ष जी आपने देखा जो हमारे साथी यहां पर बोल रहे थे और बहुत लोग, बहुत सारे प्रवक्ता, वक्ता टीवी पर मोहल्ले पर किसी की चाय की दुकान पर बात करते हैं कि प्रजातंत्र में धोखा हो रहा है, प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है ये रोज़ का काम है। हर विपक्ष में लोग बोलते हैं लेकिन मैं नहीं मानता कि देश के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि पांच

साल के बच्चे से लेकर अस्सी साल तक के बुजुर्ग ने देखा कि वो हत्या होती कैसे है। बात तो सब करते हैं लेकिन उसे देखा क्या कि कैसे एक आदमी जिसे प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर बनाया गया, कैसे हाथ में एक तरीके से जो पेन था उस पेन की जगह उसने एक छुरा पकड़ा हुआ था और वो मार्क नहीं कर रहा था वो प्रजातंत्र का गला काट रहा था। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे और उसने वो गला काटा और उसकी हत्या कर दी। ये सबने लाइव देखा। बड़ी ही अजीब बात है कि क्योंकि हम एक धर्म की बार-बार बात करते हैं सनातन की और जिसकी सबसे पहली लाइन है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो सबसे बड़ा लॉ है नेचर का वो कहता है कि जो ऊपर जायेगा उसको नीचे आना निश्चित है लेकिन भाजपा को ये बात समझ में नहीं आती। अरे एक लाख पूत, सवा लाख नाती वाला रावण खत्म हो गया तुम चीज़ क्या हो और खुले आम गदर को मचाना। सरकार चुनी किसलिये जाती है? अरे अगर पुल बनाना हो, सड़क बनानी हो, गली बनानी हो तो बनती रहती है वो तो। वो सारी सरकारें बनाती रहती है, केंद्र सरकार बना देगी बाकी जगह अधिकारी बैठा दो। अधिकारी भी कुछ न कुछ कर लेंगे। कुछ तो करेंगे जब बजट आयेगा तो। अंग्रेज भी कुछ करते थे, मुगल भी कुछ करते थे, वो भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते थे। तो फिर आपको संसद की जरूरत क्या पड़ी, देश की आजादी की जरूरत क्या पड़ गयी। बिठा लो उन लोगों को दोबारा, बिठा दो दोबारा से अंग्रेजों को, बहुत अच्छे-अच्छे पुल बनाये, संसद भवन बनाया, जहां हम बैठे हैं वो उन्होंने बनाया। हमें क्या जरूरत थी

सरकार की। सरकार की जरूरत ये थी कि एक आम आदमी को, एक ठेले वाले को, एक मजदूर को, एक रेहड़ी वाले को, एक प्रवासी को ये महसूस हो कि ये जो विधायक है, ये जो सांसद है, ये जो मंत्री है, ये जो प्रधान मंत्री है ये मेरा अंश है। ये प्रजातंत्र को बचाने के लिये जो इतनी लड़ाई होती है जो बार-बार बात होती है इसीलिये होती है कि प्रधान मंत्री में उस आदमी का एक अंश है जो वोट देता है, विधायक में वो अंश है इसलिये प्रजातंत्र को बचाया जाता है। इसीलिए एक संविधान की रचना करी गई, एक स्टेट को कुछ पावर दी गई, कुछ देश को दी गई अगर उस पे डिस्प्यूट होता है तो सैन्टर की पावर prevail करती है। अगर वो डिस्प्यूट वहां नहीं खत्म होता तो उसके लिए न्यायालय है। अब आप मुझे ये बताइये कि झुगगी टूटे हम कोर्ट जाएं, शौचालय टूटे हम कोर्ट जाएं, हमारे बिजली, पानी, सीवर के पैसे रोक दो, हम कोर्ट जाएं। हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दो हम कोर्ट जाएं। हम कोर्ट जाते रहें और कोर्ट जाकर क्या होगा साहब, कोर्ट जायेंगे तो कोर्ट कहेगा नहीं सर्विसिज दिल्ली सरकार का अधिकार है तो फिर आप क्या करोगे। आप संसद में कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल दोगे, कैसा प्रजातंत्र है साहब? बिल्कुल मज़ाक हो रहा है, किसलिए चुनाव की जरूरत पड़ गई बार-बार, देखिए कोर्ट ने कल सब कुछ देखा दूसरी तरफ के वकीलों को कुछ कहने को नहीं था फिर भी वो खड़े हुए उन्होंने अपनी बात रखी, कोर्ट में सारी डिटेल्स मंगाई और कहा भई ऐसे हम प्रजातंत्र को मरते हुए नहीं देख सकते। उसके बाद भी किसी राष्ट्रीय चैनल पर कल ये डिबेट नहीं हुई, किसी राष्ट्रीय

चैनल पर ये डिबेट नहीं हुई कि खुलेआम ऐसे प्रजातंत्र का मर्डर होते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने डिबेट नहीं करी सर। सबके सब मोदी मीडिया यही दिखाते रहे, उल्टी सीधी बातें बताते रहे और एक हफ्ते पहले तक तो बता रहे थे कि नहीं चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ है और भाजपा की तरफ से एक लाइन नहीं आई कि नहीं ये गलत हो गया या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी चाहिये थी कि इसमें हम क्या करें। मेरा अपनी बात को खत्म करते हुए सर एक सवाल है जो मेरे मन में रहा। जैसे मैंने कहा मैंने कभी ऐसे हत्या होते हुए सुनते थे लेकिन पहली बार मैंने अपने आप में ये देखा कि प्रजातंत्र का मर्डर कैसे हो रहा था। अब मेरा एक और सवाल है सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को मंगाया और चेक कर लिया। देखा क्या लकीर खींची थी, क्या करा था, क्या नहीं करा था, कैसे वो इन्वैलिड हुए। सर अगर ये ईवीएम मशीन होती तो? ये कैसे चैक होता, ईवीएम मशीन में तो वोट आ जाते, 5 आये, 10 आये, 18 आये, उनकी तरफ को तीन ज्यादा गये, तीन कम गये। इसे दोबारा चैक कैसे करा जाता। दोबारा वोटिंग करानी पड़ती और दोबारा वोटिंग में क्या होता, इसके लिये उन्होंने सेटिंग करी, तीन हमारे पार्षदों को डरा के, धमका के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके पास है ही और अपनी तरफ को कर लिया ताकि दोबारा हो तो उनके पक्ष में फैसला हो।

माननीय अध्यक्ष: कनकलूड करिये राजेश जी कनकलूड करिये।

श्री राजेश गुप्ता: तो ये सवाल आपके माध्यम से देश की कोर्ट के आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे और देश की जनता के आगे है

कि क्या आप ऐसे लोगों को दोबारा जिताओगे 2024 में, आपके छोटे से अंश को जो आप वोट देते हो, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, सांसद, विधायक बनाने का वो आपके अंश हैं, वो खत्म हो जाएंगे ये इतने खतरनाक बनने वाले हैं कि दुनिया के अंदर दंगे कराने वाले पार्टियां होती थीं बड़ी बड़ी जैसा अमेरिका के अंदर हुआ, वही हिंदुस्तान के अंदर होगा, ये दोबारा आयेंगे तो। अगर इनकी कुछ भी सीटें कम हुईं तो ये दंगे करवायेंगे। तो लोगों को समझना है इनकी पावर को खत्म करना है, ऐसे लोगों को वोट न दें जो आपके वोट की ताकत को ही खत्म कर रहे हैं। आपने बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान राजेन्द्र पाल गौतम जी, बहुत संक्षेप में राजेन्द्र जी प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिये और जो ज्यूडिशियरी से देश की जनता का विश्वास उठने लगा था उस विश्वास को बचाने के लिये जो निर्णय आया। दो निर्णय महत्वपूर्ण पिछले 15 दिन के अंदर आये। एक इलैक्ट्रल बांड का जिसका लगभग 90 परसेंट चंदा बीजेपी के पास जा रहा था जांच उसकी भी होनी चाहिये कि जिन लोगों ने चंदा दिया उनको कितने सरकारी ठेके प्राप्त हुए। और दूसरा जजमेंट ये जो आया कल जिससे लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम किया इसके लिये मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ और अपनी

बात को शुरू करने से पहले जो मेरे विद्वान साथी संजीव झा जी ने जो वक्तव्य रखा मैं उससे आगे शुरू करता हूं वो वक्तव्य मेरा भी है और वो ये है कि इस बात को सबको समझना चाहिये कि असली चोर कौन है। आपको याद होगा एक वीडियो पिछले दो तीन दिन से चल रही है। रावलपिंडी के इलैक्शन कमिशनर ने 13 विधायकों को जो 50-50 हजार, 70 हजार वोटों से जीते उन्हें हारा हुआ डिक्लेयर करके हारे हुए लोगों को जिता दिया। और आज आप समझिये कि जो प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर बनता कैसे है, ये चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश है और जब इस तरह का मेयर का चुनाव होता है तो फाइल नीचे तक नहीं रहती, प्रेज़ाईडिंग ऑफिसर किसको बनाना है ये पहले भारतीय जनता पार्टी में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद वहां के डिप्टी कमिशनर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर के पास फाइल गयी। एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ये फाइल होम मिनिस्ट्री में गयी और फिर होम मिनिस्ट्री ने देश के प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके अनिल मसीह जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी थे, एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनको बनाया, पूरा का पूरा गेम ये होम मिनिस्ट्री में रचा गया। जब वो रावलपिंडी के इलैक्शन कमिशनर कह रहे हैं कि मुझे खुलेआम रावलपिंडी के चौक पर फांसी दे दी जाये, मैंने देश के साथ गद्दारी की है, देश के लोगों के वोट के साथ गद्दारी की है तो मैं समझता हूं यही आत्मग्लानि कहीं न कहीं इस एडमिनिस्ट्रेटर को हुई थी जिसने रिजाइन किया। मैं चाहता हूं कि पूरे देश को पता लगना चाहिये न केवल अनिल मसीह पे मुकद्मा चले, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर पर मुकद्मा चलना चाहिये, देश के गृहमंत्री

जिन्होंने अनिल मसीह को अपोईट करने का जो साइन करके बकायदा उसको अपोईट किया है उस पर भी मुकद्मा चलना चाहिये चूंकि ये देश की डेमोक्रेसी को पूरी तरह इन्होंने कैप्चर कर लिया है। देश के संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है और कह रहे हैं पिछली बार का 300 पार तो 300 पार हो गयी अब की बार कह रहे हैं 400 पार, भई कौन सा सपना कौन सा ऐसा वायदा था जो आपने पूरा किया हो, कौन सा ऐसा काम है जिससे जनता इतना खुश है कि तुम्हे वोट देगी। ये भरोसा तुम्हें ईवीएम से आता है, उस ईवीएम से आता है जिसको बनाने वाली कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं ईवीएम मशीन के अंदर रही ये टाइम क्लॉक क्यों है इसीलिये है ताकि किस टाइम चोरी करवानी है चूंकि मॉक पोल भी होता है पहले। पहले मॉक पोल होता है जिसमें सारे पार्टियों के एजेंट वोट डाल के देखते हैं इसीलिये चोरी उस वक्त नहीं होती रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन के अंदर इसलिये है उसके अंदर डेट और टाइम तय कर दिया जाता है किस टाइम से किस टाइम के बीच चोरी करके और ये वोटें बीजेपी को देनी हैं। मैं आपके माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है इसलिये मैं लंबा बोलने की बजाए पुनः देश के मुख्य न्यायाधीश जी को भी और देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी, देश के लोकतंत्र को संविधान को बचाने के लिये और ज्यूडिशियरी में लोगों का भरोसा कायम हो उन्होंने वो जो काम किया है उसको मैं सैल्यूट करता हूं धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे

जो बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, बिधूड़ी जी, जनरैल जी, सिर्फ दो तीन मिनट, बहुत संक्षेप में दो मिनट।

श्री जनरैल सिंह: शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस ऐतिहासिक फैसले जिसमें लोकतंत्र की रक्षा की गयी है, इस बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट पर बोलने के लिये मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर चंडीगढ़ इलैक्शन से मैं काफी करीब से जुड़ा रहा, 2021 के अंदर हमने बहुत मेहनत की, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और उसका नतीजा हमें कल मिला है। 2022 की जनवरी के महीने में जब पहली बार ये इलैक्शन हुए थे 27 दिसम्बर 2021 को इस चुनाव के नतीजे आये, 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली उसी दिन आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की लार्जैस्ट पार्टी बन के आई थी। उसूलन तो 2022 के जनवरी के महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बन जाना चाहिये था पर ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार देश के अंदर लोकतंत्र की आये दिन हत्या करती है वो हम कई सालों से देख रहे हैं, 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलीं 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलीं, 8 सीटें कांग्रेस को मिलीं और एक सीट अकाली दल को मिली। लॉजिकली तो हमारा सीधा सीधा मेयर बन रहा था पर 2022के अंदर भी इन्होंने एक वोट हमारी इसी तरीके से इन्वैलिड की जिस तरीके से आठ वोटें हमारी इन्होंने इस साल इन्वैलिड की है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट

ऑफ इंडिया से ये भी गुहार लगाना चाहूंगा कि उस साल के नतीजों का भी एक बारी निरीक्षण कराया जाए और उस साल के नतीजों में भी ये ये पायेंगे कि साफतौर पर एक वोट को ऐसे ही टिक लगाकर के इन्वैलिड कर दिया गया था, नहीं तो 2022 के अंदर ही हमारा ये मेयर चंडीगढ़ के अंदर होता। तो आज वो सारे साथी जिन्होंने तब जाकर मेहनत की थी, बहुत इस चीज पर तसल्ली व्यक्त कर रहे हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले ही नहीं, पूरे देश के वो लोग जो चुनावी प्रक्रिया में एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं वो सब के दिल में कल का ये फैसला आने के बाद बहुत तसल्ली है। जब इस साल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये चुनाव मिलकर लड़ने का निर्णय लिया तभी से बीजेपी के होश उड़े हुए थे स्पीकर साहब। हमारे एक-एक काउंसलर को किसी भी तरीके से तोड़ने की, डराकर, धमकाकर, खरीदकर, बेहिसाब कोशिशें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, क्योंकि कोर्ट में तो हम 2022 के अंदर भी गये थे, एक साल यूं ही निकल गया, फिर से मेयर की इलैक्शन आ गई, 23 के अंदर इन्होंने फिर horse trading करके अपना मेयर चंडीगढ़ के अंदर बनाया। और इस साल जब तय हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, उस दिन से इनके होश उड़े हुए थे, जिस दिन चुनाव की पिछली तारीख थी तो प्रजाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह बता रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना एक टेलीफोनिकली मैसेज कर दिया, क्योंकि नंबर पूरे नहीं हुए थे कि जी मेरी तबीयत खराब है,

सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने उस दिन इलैक्शन पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद जब 30 जनवरी को इलैक्शन हुए, मैं खुद वहां पर मौजूद था चंडीगढ़ में, स्पीकर साहब जिस टाइम हमारे एलओपी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि आप पेन लाल या हरे रंग का इस्तेमाल करें, तो वहां उनसे पूछा गया जी आप पेन कौन से रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी मैं नीले रंग का ही इस्तेमाल करूंगा। अब प्रजाइडिंग ऑफिसर के आगे कोई बोल नहीं सकता। इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी उन्होंने पेन का कलर चेंज नहीं किया क्योंकि नीले रंग की स्टैम्प लग रही थी और नीले रंग के पेन से ही हेराफेरी करनी थी। तो वहीं से तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत घटिया साजिश आज के इस चुनाव को जीतने के लिए रच रखी है। किस तरीके से 8 वोटों को इन्वैलिड करार दिया गया और उस दिन बहुत निराशा हुई स्पीकर साहब, बहुत, पूरे देश में इस एक निराशा का माहौल बन गया कि बीजेपी कितनी नीचे स्तर तक, कितनी नीचे हरकतें, कितनी घटिया हरकतें कर सकती है चुनाव को जीतने के लिए। लोगों की मर्जी के खिलाफ, चंडीगढ़ के लोगों की मर्जी के खिलाफ 8 वोटों को इन्वैलिड करार देकर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्ती मेयर बनाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज की सुनवाई की और बहुत शानदार तरीके से, एक-एक तथ्य पर गौर करते हुए, उन्होंने पिछले हफ्ते ही ये बोल दिया था कि हम इस तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे, उस दिन से एक उम्मीद की किरण जागी थी और कल जो निर्णय आया उसने बहुत

पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल बनाया। पर भारतीय जनता पार्टी वालों से देश को यही उम्मीद होनी चाहिए कि

‘जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर,
तो लाशों के ढेर देखकर हैरान क्यों हो।’

ये सारे देश को उम्मीद होनी चाहिए कि ये कत्लेआम का हुनर देखकर ही चुना था, ये इंसान मारने में शर्म नहीं करते पर अब तो इंसानों से बढ़कर इंसानों के लिए जो संविधान बनाया गया, जो लोकतंत्र बनाया गया है उसको मारने तक ये हिचक नहीं कर रहे हैं तो देश को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, निर्णय का समय बहुत जल्दी आने वाला है कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को चुनना है या लोकतंत्र को मजबूत करने वालों को चुनना है। क्योंकि समय की सीमा है स्पीकर साहब, मैं जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले का स्वागत करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं, वहीं सभी देशवासियों को बधाई भी देता हूं कि इस मुश्किल दौर में, इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले से आई है। आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मौके पर मुझे बोलने का समय दिया थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। कल जब ये खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमारे तक आई, खुशी तो बहुत हुई

अध्यक्ष जी, मगर खुशी से ज्यादा आज चिंता है पूरे देश में, आम आदमी पार्टी में चिंता है कि जो केंद्र सरकार कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास केंद्र में सरकार है, दर्जनों राज्यों में सरकार है, पंचायतों में है, कॉरपोरेशंस में है, हर जगह सरकार है लगभग। उसके बावजूद चंडीगढ़ जैसे छोटे से मेयर के इलैक्शन में सबसे छोटी पार्टी के साथ लड़ते हुए कैमरे के ऊपर, कैमरे में कैद बेईमानी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई, ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है अध्यक्ष जी। जो पार्टी इस हद तक एक छोटे से चुनाव में, अध्यक्ष जी, मैं ये कहता हूँ कि 90 प्रतिशत लोगों को तो भारत में ये भी नहीं पता होगा कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है, हमें ही नहीं पता था कुछ सालों तक। 14 लाख की आबादी है चंडीगढ़ की। एक साल के लिए एक छोटा सा मेयर चुना जाता है, उस इलैक्शन के अंदर केंद्र सरकार की नीयत इतनी खराब हो गई, तो ये जो है बहुत चिंता की बात है अध्यक्ष जी। ऐसी केंद्र सरकार जो पूरे देश में चुनाव कराती है, जब कैमरा नहीं लगा होता होगा तो ये केंद्र सरकार क्या करती होगी, ये बड़ी चिंता की बात है और क्यों है अध्यक्ष जी, जब देश आजाद हुआ तो आजादी का मतलब क्या था, आजादी का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस बनवा दिया, मोदी जी ने ट्रेन बनवा दिया, अंग्रेज भी बनवाते थे, अंग्रेजों ने भी पार्लियामेंट हाउस बनवाया, अंग्रेजों ने ट्रेनें बनाई, अंग्रेजों के बंदरगाह बनाये, अंग्रेजों ने सड़क बनाई, ये कोई न आजादी है। आजादी ये थी कि हम अपनी खुद की सरकार चुने, लोग अपनी सरकार चुने,

ये आजादी थी और कुछ नहीं थी आजादी। और इस आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, सबने जान दी और उससे सौ साल पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, सब लोगों ने जान दी, कुर्बानी दी इस चीज के लिए कि देश के अंदर आजादी के बाद जो चीज एक, बिल्कुल मूल चीज जो बदलेगी वो ये है कि लोग अपनी सरकार खुद चुन सकेंगे और अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो देश को चलायेगी। आज उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल अध्यक्ष जी खड़ा हो गया है। और कितनी बार कोर्ट जायेंगे, समस्या ये है। आज तो चलो हम चंडीगढ़ में थे, हम हाई कोर्ट चले गये, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, हम सुप्रीम कोर्ट आ गये, सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया, मगर कितनी बार जाये अध्यक्ष जी। इस छोटे से इलैक्शन को कराने के लिए हम कई बार हाई कोर्ट गये। पहले तो इलैक्शन कराने के लिए होई कोर्ट गये, हाई कोर्ट ने कहा फ्री एंड फेयर इलैक्शन होना चाहिए, विडियो रिकॉर्डिंग होगी तो ये विडियो रिकॉर्डिंग हुई। प्रजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो गये, हम फिर हाई कोर्ट गये। नई डेट दे दी फरवरी की, हम फिर हाई कोर्ट गये, फिर 30 जनवरी की डेट दे दी, उसमें बेइमानी हुई, हम फिर हाई कोर्ट गये, हाई कोर्ट ने कहा हम स्टे नहीं देंगे, 3 हफ्ते लंबी डेट दे दी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गये। अध्यक्ष जी, हम ये ही करते रहेंगे क्या? क्या इस देश के अंदर सिर्फ अब कोर्टों से ही फैसले होंगे, लोग जो फैसला लेते हैं उसको कौन देखेगा? इलैक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होंगे इस देश के अंदर ये चिंता आज पूरे हाउस की है

अध्यक्ष जी। खुशी है मगर खुशी से बड़ी हमारी चिंता है, इस केंद्र सरकार के ऊपर लगातार वर्षों से ये आरोप लगते आ रहे हैं अध्यक्ष जी कि ये इलैक्शन के अंदर बड़ी धांधली करते हैं। और आज जब चंडीगढ़ के मेयर के इलैक्शन में इनकी धांधली सबके सामने पकड़ी गई तो अध्यक्ष जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज हाउस से गायब हो गये, आप ये देखिये कितनी बड़ी बात है। आज उनको खड़े होकर कहना चाहिए था कि मेरी पार्टी ने बेइमानी करी, मैं बहुत शर्मिदा हूं मगर आज वो गायब हो गये, इससे ये पता चलता है अध्यक्ष जी जो चोरी की, वो चोरी पकड़ी गई और इनके मन में उस चोरी के लिए थोड़ा सा भी मलाल नहीं है, थोड़ा सा भी अपराध बोध नहीं है। और उससे बड़ी चिंता की बात अध्यक्ष जी ये है कि देश के अंदर करोड़ों लोगों की एक ऐसी गैज खड़ी हो गई है जो अपने आपको भाजपाई कहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, पार्क में बात कीजिए, चाय की दुकान पर बात कीजिये, कहते हैं नहीं राजनीति में तो ऐसा होता है, सही कर रहे हैं मोदी जी। ये हालत हो गई है हमारे देश के आज इंटेलेक्ट की कि आज इस तरीके से नैटिव बना दिया गया है कि उनके नेता खुल्लम-खुल्ला चोरी करते हुए, डकैती करते हुए, बेइमानी करते हुए, छल कपट करते हुए पकड़े जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कह रहा है, नहीं-नहीं-नहीं, ठीक है, ऐसे तो करना ही पड़ता है। तो ये जो है देश के लिए बड़ी चिंता की बात है इसीलिए ये ही बात कहककर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद जी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी।

माननीय पर्यावरण मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र की रक्षा करते हुए भारत के अंदर वर्तमान दौर में जो एक संकट का दौर है, उस दौर में जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला दिया, उस पर चर्चा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनिल मसीह जो चुनाव अधिकारी थे उनके कारनामों पर चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर अनिल मसीह जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का इतनी बड़ी गड़बड़ी करके, बेइमानी करके ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीताने में क्या फायदा था, क्यों अनिल मसीह ने एक बेइमानी का कांड किया। अध्यक्ष महोदय, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे, उस पूरे सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय कैमरे के सामने चुनाव अधिकारी- अनिल मसीह बैलेट पेपर पर निशान लगाकर के बेइमानी से भारतीय जनता पार्टी को जीताने का ऐलान करते हैं उसके ठीक, अभी अनिल मसीह ऐलान करके उठ भी नहीं पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जबरदस्ती उठाकर के लाकर के निर्वाचित अवैध तरीके से जो मेयर था उसे कुर्सी पर बिठा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं सिलसिला रूकता है, अनिल मसीह बेइमानी का कांड चंडीगढ़ में करते हैं, पीछे जिसको चुनाव घोषित, जीता हुआ घोषित करते हैं तुरंत लाकर बिठा दिया जाता है और एक मिनट नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विट करके घोषणा

करते हैं कि इंडिया एलायंस की पहले चुनाव में पराजय हो गई। अनिल मसीह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताना-बाना रिमोट कंट्रोल चारों तरफ किया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले ने इस देश के अंदर एक आशा की किरण जगाई है लेकिन अध्यक्ष महोदय हमें इस बात की खुशी है कि आज लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के जुबान पर ताले लग गये हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, कल से मैं देख रहा हूँ जो हर बात में गालियाँ देने के लिए प्रवक्ताओं की फौज है, आज कल से टीवी चैनल से गायब हैं, अखबारों में बयान नहीं आ रहे भारतीय जनता पार्टी के। आज विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के सदन छोड़कर के भागने पर मजबूर हो गये और देश के प्रधानमंत्री चुप हो गये हैं। कहते हैं बेइमानों को जेल में जरूर डालूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आज सर्वोच्च न्यायालय ने सारे फैसले सुना दिये हैं। हर बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दुहाई देते हैं, अदालत जो कह रही है उसको आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कानून को नहीं मानते, अदालत को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बर्खास्त करो और इस बात के लिए सीबीआई को भेजो, अनिल मसीह को पैसा किसने दिया था, अनिल मसीह को धमकी किसने दी थी, अनिल मसीह को लालच किसने दिया था। क्या सीबीआई जांच करने को तैयार होगी, क्या ईडी जांच करने को तैयार

होगी और अगर नहीं होती है तो इस सदन के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं इसकी न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए। इस देश के अंदर अगर इसकी न्यायिक जांच होती है, अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अनिल मसीह का मसीहा जो चंडीगढ़ के अंदर षड़यंत्र करने में सारे शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल है, सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ एक न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए जिससे सच्चाई का पता चल सके। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चौराहे पर नहीं दुनिया के अलग-अलग मंचों पर जाकर के कहते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है लेकिन अफसोस है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से सरेआम इस लोकतंत्र की हत्या की गई है, आज वो सबके सामने है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये तो एक छोटा सा घटनाक्रम जो सामने आया है देश के, आज पूरे देश के अंदर चौतरफा ये कांड हो रहा है, चौतरफा ये कांड हो रहा है। आज देश के अंदर चाहे वो दिल्ली के अंदर अभी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की, दिल्ली के अंदर चाहे वो ऑपरेशन लोटस चलाने की बात हो, यहां पर कोशिश हो रही है।

आपको अगर याद होगा दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हुआ था, सबसे ज्यादा बहुमत की सीट जीतकर के आई आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मा की तरह घूम-घूम कहते थे मेयर हम बनायेंगे, मेयर हम बनायेंगे, मेयर हम बनायेंगे। बहुमत हमारे पास है मेयर तुम बनाओगे, किस कलाकारी से

बनाओगे, भारत के संविधान ने नया कौन सा रास्ता खोल दिया है मेयर तुम बनाओगे, उसी कान्फिडेंस से वो कहते थे, दिल्ली में हमने नहीं चलने दी। चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने जाकर के इस कांड को किया है और ये मर्डर केवल चंडीगढ़ में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अंदर डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है, सरेआम विधायकों की खरीद-फरोख्त की गई, कर्नाटक के अंदर विधायक खरीदे जा रहे, झारखंड के अंदर दो दिन तक, जिस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री-हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसी दिन शाम को उसी समय जाकर के बहुमत का अपना पत्र सौंप दिया विधान सभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को सौंप दिया था। राज्यपाल ने सरकार वहां बनने नहीं दी, शपथ नहीं दिलाया, इंतजार करते रहें वहां भी हम खरीदेंगे। बिहार के अंदर इन्होंने खरीद-फरोख्त की है।

देश के अंदर हर कोने में इनका एक सिद्धांत चल रहा है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव भी बेइमानी से जीतना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए अगले लोकसभा का, जमानत प्रधान की होगी और प्रधानमंत्री की भी, जो सपना लेकर के भाजपा घूम रही है उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आज के दौर में किया क्या जाए? जो ईमानदार है उसको जेल में डालने की कोशिश हो रही है। एक सूत्र बनाया गया है या तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो या तो चुप हो जाओ, नहीं तो बिक जाओ और नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज जो परिस्थिति बन रही है देश के

अंदर, पूरे देश के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, आज अगर चुप रह गये तो कल तुम्हें चुप करा दिया जायेगा, बोलने लायक कोई नहीं बचेगा क्योंकि चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है। लोकतंत्र के हर मोर्चे पर हमला हो रहा है, चाहे जुडिशरी हो, उसके ऊपर हमला हो रहा है, चुनाव आयोग हो, उसके ऊपर हमला हो रहा है, चुनाव हो उसके ऊपर हमला हो रहा है। कल बंगाल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरेआम एक आईपीएस अधिकारी को कहा कि तुम खालिस्तानी हो, ये हिम्मत इस देश के अंदर भाजपा के नेताओं की पैदा हो गई। एक अधिकारी को ड्यूटी करते हुए इसलिए उसे तुम खालिस्तानी बोलने की हिम्मत करते हो की वो सरदार है और पगड़ी लगाया हुआ है। तुम्हें नहीं पता इस मुल्क के अंदर आजादी की लड़ाई में एक व्यक्ति को शहीदे आजम का सम्मान मिला है उसका नाम भगत सिंह है जो एक सरदार परिवार में पैदा हुआ था और हंसते-हंसते फांसी के नंदे को चूम लिया था। भूल गये करतार सिंह सराबा को, भूल गये तुम ऊधम सिंह को जिसको देश अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है उस पगड़ी को उसको तुम्हें अपमानित करने में शर्म नहीं आती है। दो मिनट में किसानों के लिए कील तुमने बिछा दिया चारों तरफ देश के अंदर, चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ तुमने बेरिकेट लगा दिये, दीवारें खड़ी की दीं, दिखा क्या रहे हो? कल अगर इस देश के अंदर किसी भी कीमत पर अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से पार सीट आती हैं इस देश में कोई जुबान नहीं खोल पाएगा और अध्यक्ष महोदय जर्मनी का इतिहास बताता है, मैं भाजपा के उन नेताओं

से भी कहना चाहता हूं मजबूरी में ही सही अगर आज चुप हो कल तुम्हारी भी हत्या की जाएगी क्योंकि इस देश के अंदर जिस रास्ते पर भारत को लेकर के जाने की कोशिश हो रही है कल कुछ धर्म के लोगों पर हमला हुआ, आज विपक्ष पर हमला हो रहा है, इस तानाशाही की विजय यात्रा अपनी पार्टी के लोगों की हत्या करके ही पूरी होती है क्योंकि विपक्ष अगर खत्म हो जाएगा तो भाजपा के अंदर जो भी नेता बोलने की जुर्रत करेगा कल मारा जाएगा और कोई चूं बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए वक्त है अगला जो दो महीना है इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, सबको सोचना पड़ेगा देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आज नहीं खड़े हुए तो कल खड़े होने लायक नहीं बचेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गीता में एक श्लोक है 'यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।' इस श्लोक का मतलब है भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ही नहीं कह रहे अर्जुन के जरिये पूरी सृष्टि को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब-जब पृथ्वी के ऊपर धर्म को कुचला जायेगा और जब-जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा तब-तब मैं उत्पन्न होऊंगा, तब-तब मैं अवतार लूंगा। एक तरह से भगवान ने मानव जाति को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है। कई ऐसे मौके आते हैं मानव इतिहास में जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और लोगों को लगने लगता है कि सच्चाई से कुछ नहीं होगा,

ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, अधर्म करने से ही होगा, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अच्छे लोग उम्मीद खो बैठते हैं, ऐसे मौकों के लिए भगवान ने इस मानव जाति को ये भरोसा दिया है कि अगर ऐसा मौका आएगा तब-तब मैं मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव जाति को उस परिस्थिति से निकालने के लिए मैं अवतार लूंगा या उत्पन्न होऊंगा। ये बहुत बड़ा भरोसा है भगवान का मानव जाति को। आज हमारे देश के अंदर जो घटित हो रहा है ये कुछ उसी तरह की परिस्थिति है। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है। चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है, इतना अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला है कि लोगों को लगने लगा है, आपस में चर्चा करने लगे हैं कि यार अब ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है, अब सच्चाई से कोई फायदा नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर चलने से कोई फायदा नहीं है और लोग देख रहे हैं इतने बड़े-बड़े षड़यंत्र चल रहे हैं, इतने बड़े-बड़े कुकर्म चल रहे हैं, बड़े से बड़े स्तर के ऊपर चल रहे हैं। लोग देख रहे हैं जो लोग कुकर्म कर रहे हैं, उनकी तो तरक्की हो रही है। देश में 75 साल के बाद इस देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य की उम्मीद देने वाला मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर है, धर्म जेल के अंदर है और हमारे देश की बेटियों को, मां-बहनों को छेड़ने वाला ब्रजभूषण सिंह सत्ता का सुख भोग रहा है। आज इस देश के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाला, गरीबों को दवाईयां दिलाने वाला सत्येन्द्र जैन जेल के अंदर है और चुन-चुन के इस देश के सबसे बड़े कुकर्मी सबसे भ्रष्टाचारी हेमंत विश्वशर्मा, शुभेन्दु अधिकारी, मुकुल रॉय,

नारायण राणे, भावना गावली, अशोक चव्हाण, यशवंत जाधव, यामनी जाधव, छगन भुजबल, अजित पवार, फुल्ल पटेल, गोपाल कांडा पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है चुन-चुनकर, चुन-चुनकर इस देश के सबसे कुकर्मि और सबसे भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराके वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ईमानदार लोग जेल के अंदर हैं। आज इतना ज्यादा अधर्म हो गया है चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है खुलेआम एमएलएज को खरीदा जा रहा है। हमारे एमएलएज को 25-25 करोड़ रुपये ऑफर किये गये। एमएलएज को खरीद-खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। कर्नाटक में एमएलए खरीदे गये, गोवा में एमएलए खरीदे गये, महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे गये, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे गये, नॉर्थ-ईस्ट के अंदर एमएलए खरीदे गये, उत्तराखंड में एमएलए, खुलेआम एमएलए खरीदे जा रहे हैं करोड़ों-करोड़ों रुपये के काले धन से एमएलए खरीदे जा रहे हैं, सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं, लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है धर्म से। चारों तरफ अधर्म का इतना बोलबाला हो गया है और ये जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जीता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलैक्शन कमिशनर की आत्मा जाग गई जिसने कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे उनको जीता दिया जो हार रहे थे। तो ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने

अचीव किया था हासिल किया था कड़ी मेहनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सबकुछ खत्म कर दिया। आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े ये करेंगे। ईवीएम में धांधली करनी पड़े ये करेंगे। ईडी पीछे लगानी पड़े ये लगाएंगे। सरकारें गिराने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे। आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक-एक-एक करके ये जेल में डालते जा रहे हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। आज इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब चारों तरफ चर्चा है अगला आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं 370 कहने का मतलब यह है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है वो कह रहे हैं तुम जाओ भाड़ में 140 करोड़ लोग गये तेल लेने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और न तुम्हारा वोट चाहिए घर बैठना 370 सीट हमारे पास मशीन है, मशीन से 370 सीटें आ रही हैं हमारी। जिस दिन इस देश के अंदर लोगों की जरूरत न पड़े, जनतंत्र के अंदर वोटों की जरूरत न पड़े, देश ही नहीं बचेगा। तो लोग देख रहे हैं इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्म ही अधर्म हो गया इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्म ही अधर्म हो गया है। जो इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें काम करना चाहती हैं उनको काम नहीं करने देते। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि गरीबों की दवाईयां रोक दी गई, अस्पतालों के अंदर गरीबों की दवाईयां रोक दी गई। गरीबों के टैस्ट रोक दिये गये, गरीबों को मरने के लिए

सड़कों के ऊपर बेहाल छोड़ दिया गया। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा की मोहल्ला क्लीनिक के अंदर जहां गरीब जाकर अपना इलाज कराता है वहां की बिजली रोक दी गई, वहां के डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई, वहां पर काम करने वाले नर्सों-कंपाउंडरों की तनख्वाह रोक दी गई, वहां के टैस्ट रोक दिये गये। इससे बड़ा हमारे हिन्दू धर्म में कहा गया है कि पानी पिलाने का धर्म होता है इन लोगों ने तो दिल्ली का पानी भी रोक दिया उसमें भी इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। तो लोग देख रहे हैं जितनी सरकारें हैं पंजाब के अंदर हम जितने काम करने की कोशिश करते हैं पंजाब भगवान की दुआ से फुल स्टेट है उतना ये नहीं कर पाते, वहां भी इन्होंने हस्तक्षेप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी अपोजिशन तमिलनाडू की ले लो, वेस्ट बंगाल की ले लो, केरला की ले लो, कर्नाटक की ले लो हर जगह ये लोग अपनी टांग अड़ाते हैं, काम नहीं करने देते ये लोग। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं बताओ क्या कसूर है जी दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है आने दो दिल्ली में हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। संविधान के आर्टिकल-19 के अंदर अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है। किसानों को नहीं आने देते न उनकी फसलों का दाम, वो क्या मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए, बिलकुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा

बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है दर-दर की ठोकें खा रहा है। व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुगियां एक के बाद एक झुगियां तोड़ी जा रही हैं। तो खुलेआम इतना अधर्म हो गया, चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तय किया कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा। समय आ गया है जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा और मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा और पिछले कुछ दिनों की घटनायें ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने की और उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। सुबह वोटिंग पड़ी, वोटिंग पड़ने के बाद एक प्रजाइडिंग ऑफिसर था पीठासीन अधिकारी, अनिल मसीह इन्हीं का आदमी था अनिल मसीह तो मोहरा है पीछे तो वो हैं, उन्हीं का आदमी था। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हाल के अंदर द्रोपदी का चीरहरण करेंगे। उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीर हरण करेंगे पूरी प्लानिंग करके आए थे। उसने तय किया कि मैं असली वोटों के ऊपर उनको ठप्पे मार-मार के डिफेंस कर-करके उनको इनवेलिड घोषित कर दूंगा और हारे हुए को जिता दूंगा। अब वहां पर श्री कृष्ण जी पहुंच गये द्रोपदी का चीर हरण रोकने के लिए, उस कमरे में दिखाई नहीं दिये किसी को, अदृश्य थे लेकिन थे वहां पर। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो वीडियो में वहां जितने भी बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ

करो, कैमरे देखे आपने वीडियो सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए, श्रीकृष्ण जी वहां मौजूद थे उन्होंने कैमरे ऑफ नहीं होने दिये। इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की, उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो पूरी दुनिया के अंदर हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। जो लोग द्रोपदी का चीरहरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, भगवान श्रीकृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीरहरण करके छोड़ दिया। और अध्यक्ष महोदय उसके बाद की जो घटनाक्रम है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला। हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा की जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं न कहीं श्रीकृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस आफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे हों। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस आफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिये बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो ये दिखाता है कि अब हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का

बहुत-बहुत शुक्रिया। हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बैंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश के जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ-साफ मैसेज दे दिया भगवान ने बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने, सबने वीडियो देखा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले एक महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है बीजेपी चुनाव चोरी करती है। ये कोई संयोग नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हमने तो ऐसे सोचा था उस दिन कि ऐसे ही हो जायेगा। तो एक छोटे से चुनाव ने पूरे देश के अंदर सारे देश को हिला दिया, कुछ न कुछ तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान का संदेश है कि मैं आ गया हूं। बीजेपी पाप कर रही है, बीजेपी अधर्म कर रही है अब ये नहीं चलेगा। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो। भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति हमारा कल्चर 3

हजार, 4 हजार साल पुराना है डर के मत बैठो, खड़े हो। आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो। कई लोगों को इस देश के अंदर लगता है कि अब तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई वोट डालकर क्या फायदा है। भगवान कह रहा है बिल्कुल नहीं, वोट डालने जाओ ईवीएम को मैं संभाल लूंगा। सारे जने वोट डालने जाओ, कोई बिना वोट के मत रहना। वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो इनके खिलाफ खड़े हो भगवान तुम्हारे साथ है। जैसे भगवान ने इनको बेनकाब किया चंडीगढ़ के चुनाव में भगवान आने वाले समय में भी इनको बेनकाब करेगा और सत्य का साथ देगा हताश होकर मत बैठो। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ हो, आप पाप के साथ हो या पुण्य के साथ हो। जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा तो एक बार तो लगा की अधर्म जीत गया। जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा एक बार तो लगा की अधर्म जीत गया। जब दुर्योधन का राज्य आया, जब कंस का राज्य आया, जब रावण की अति हुई तो एक बार तो लगा की अधर्म जीत गया लेकिन अंत में तो धर्म जीता। आज भी जब चारों तरफ बीजेपी का अधर्म फैला हुआ है तो एक बार लगता है कि अधर्म जीत गया। ऐसे लगता है न कई बार कि ये तो हार ही नहीं रहे जी। एक बार लगता है अधर्म जीत गया लेकिन धर्म जीतेगा, अंत में धर्म जीतेगा। जो-जो धर्म के साथ हैं, जो-जो देशभक्त हैं, जो-जो पुण्य के साथ हैं, जो-जो लोग भगवान राम के भक्त हैं, जो-जो शिवजी के भक्त हैं, जो-जो हनुमान जी के भक्त हैं,

जो-जो श्रीकृष्ण के भक्त हैं वो देश के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं। भारत माता की जय, जय श्रीराम, जय श्रीराम।

माननीय अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 22 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भोजन की व्यवस्था है कृपया भोजन अवश्य करें।

(सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 22 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।
